

श्वेता विजन

“नजरिया साफ, ख़ब्बरें निष्पक्ष”

हिंदी दैनिक समाचार पत्र

3

शुक्रवार 25 सितम्बर 2026

हैदराबाद से प्रकाशित

WEB SITE : Shwetha.co.in

संपादक : रघुराम राजू कालीदिंडी

पुष्ट - 1 | अंक - 10 | वर्ष - 8 | मूल्य - 3रु

केंद्र सरकार ने पिछली और चल रही भर्तियों में प्रशासनिक अराजकता से बचने के लिए 2 साल की मोहलत मांगी है. पढ़ें, पूरी खबर.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार की उस याचिका पर विचार करने के लिए सहमति दे दी है, जिसमें कोर्ट को 11 मार्च को फैसले को भविष्य की तारीख से लागू करने की मांग की गई है. कोर्ट ने अपने उस फैसले में कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी क्षेत्र में काम करने वाले माता-पिता को वेतन या आय को अपने आप में अन्य पिछड़ा वर्ग (व्यवस्था) के 'क्रीमी-लेयर' से बाहर रखने का एकमात्र पैमाना नहीं माना जा सकता.

अदालत में केंद्र सरकार का पक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भारती ने रखा. उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश सुर्यकांत और जस्टिस जयपाला बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने अपनी दलीलें पेश कीं. भारती ने तर्क दिया कि इस फैसले को भविष्य के लिए लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने कोर्ट द्वारा तय किए गए इस कानून को पूरी तरह लागू करने और पिछली व चल रही भर्ती प्रक्रियाओं में किसी भी तरह की बाधा को रोकने के लिए दो साल का समसमय अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की दलीलों पर ध्यान दिया कि अलग-अलग हाई कोर्ट्स ने इस फैसले से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी है. भारती ने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न हाई कोर्ट्स से मामलों को ट्रांसफर कर के सर्वोच्च अदालत या किसी एक हाई कोर्ट में भेजने की मांग करते हुए याचिका दायर की है.

केंद्र सरकार ने कहा कि यह इस अदालत द्वारा तय किए गए कानून को लागू करने पर केवल 2 साल की सीमित रोक का अनुरोध कर रही है.

ताकि प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रतिस्पर्धी अधिकारों को व्यवस्थित किया जा सके.



केंद्र सरकार के एक नोट में कहा गया, "इस फैसले को पिछली और चल रही भर्तियों पर लागू करने से उन लोगों के प्रतिस्पर्धी अधिकारों को भारी नुकसान पहुंचेगा जो इस मुकदमे में पक्षकार भी नहीं थे. इससे नियुक्त हो चुके लोगों या उम्मीदवारों की बरिष्ठता और कैंडर आबंटन को दोबारा खोलना पड़ेगा, जिससे पूरी तरह से प्रशासनिक अराजकता पैदा हो जाएगी." नोट में आगे कहा गया कि भविष्य से कानून लागू करने का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 32, 141 और 142 के तहत सर्वोच्च अदालत की शक्ति में निहित है. नोट में कहा गया है कि भविष्य से कानून लागू करने का सिद्धांत बीते सालों में एक लचीले न्यायिक उपकरण के रूप में विकसित हुआ है.

यह उस सामान्य नियम के अपवाद के तौर पर सामने आया है जिसके तहत अदालत केवल उस कानून की घोषणा करती है जो हमेशा से अस्तित्व में था— वह कानून "बनाती" नहीं है. ताकि एक घोषणा सामान्य रूप से पिछली तारीख से प्रभावी हो

सके, यानी उस प्रावधान की शुरुआत से जिसकी व्याख्या की गई है.

नोट में आगे कहा गया, "हालांकि, ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें अदालत पाती है कि प्रतिस्पर्धी अधिकारों को व्यवस्थित करने, प्रशासनिक अराजकता से बचने या अदालती कार्यवाहियों को बोझा खोले जाने से रोकने के लिए सामान्य नियम में अपवाद जरूरी है, और वह अपने सामने मौजूद मामले के हिसाब से उपयुक्त निर्देश पारित करती है."

नोट में आगे कहा गया कि ऐसा कोई तय तरीका या नियम नहीं है जिसके तहत यह अदालत इस न्यायिक उपकरण का इस्तेमाल करती है. नोट में कहा गया, "इस अदालत के पास संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने फैसले को भविष्य की तारीख से प्रभावी घोषित करने की शक्ति है, यदि इस फैसले को भविष्य की तारीख से लागू नहीं किया गया, तो उन कर्मचारियों या नियुक्त हो चुके लोगों पर कई गंभीर, अन्यायपूर्ण और अनचाहे परिणाम भुगतने पड़ेंगे जो इस मुकदमे में पक्षकार भी नहीं थे, और इससे पूरी तरह से प्रशासनिक

अच्छ के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मांगा ब्र का इस्तीफा कॉकरोच जनता पार्टी ने दी 48 घंटे की चेतावनी

नई दिल्ली: मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेसिफ रिवीजन' (प्) को लेकर चुनाव आयोग के भीतर मतमेदों की मौखिका रिपोर्ट आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. इसी कड़ी में गुरुवार को राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (अच्छ) ने मुख्य चुनाव आयुक्त (म्व) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके इस्तीफे के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. दरअसल, दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी नेताओं अभिजीत दीपके, सीरम दास और आशुतोष रांका ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने और मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली करने का आरोप लगाया है.



इसके साथ ही, अच्छ ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, तो पार्टी दिल्ली से एक बड़े देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करेगी. अच्छ के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, "बीजेपी 2024 के चुनावों में बहुमत हासिल

नहीं कर पाई, बहुमत न मिलने पर उनमें घबराहट फैल गई. '400 पार' का नारा देने के बाद वे 240 सीटों पर सिमट गए. इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि देश का मूड बदल रहा है और क्षेत्रीय ताकतें बहुत गजबूरी से उभरकर सामने आई हैं. चाहे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हों, एनसीपी, एम के स्टालिन, पिनाराई विजयन, अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी, ये सभी मुख्यमंत्री एक-एक करके हार गए हैं. यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता. आप एक पैटर्न देख सकते हैं. ये सभी मुख्यमंत्री एक साथ आए थे और 2024 में एकजुट होकर प्रचार किया था. वे एक-एक करके कैसे बाहर हो गए? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की

लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक, 8 मामलों में थ्रू, एक में प् जांच का आदेश, 12 का निस्तारण

बेहरादून: उत्तराखंड में जमीन से जुड़े विवाद और कथित फर्जीबाड़े लगातार प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं. आज 24 सितंबर गुरुवार को गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में बेहरादून स्थित आयुक्त शिविर कार्यालय में हुई लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक हुई. बैठक में गढ़वाल मंडल के विभिन्न जिलों से सामने आए 56 मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई. आठ मामलों में मुक, दमा दर्ज बैठक में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, फजी दरतावेजों के आधार पर भूमि हस्तांतरण, अनधिकृत प्लॉटिंग और जमीन की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी से जुड़े मामलों पर अधिकारियों से जवाब मांगा गया. समीक्षा के दौरान 12 मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि 8 मामलों में प्राथमिकी दर्ज



कराने के निर्देश दिए गए हैं. एक मामले में एसआईटी जांच के आदेश दिए गए, जबकि बाकी 35 मामलों में संबंधित अधिकारियों को अभिलेखों और तथ्यों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है. लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक के बाद 8 मामलों में थ्रू (फ्ट टीतज) मई 2026 में 125 मामलों की समीक्षा की गई. लैंड फ्रॉड के मामलों का हालिया आंकड़ा बताता है कि यह समस्या लगातार प्रशासनिक एजेंडे में

बनी हुई है. मई 2026 में गढ़वाल मंडल की लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में कुल 125 मामलों की समीक्षा किए जाने की जानकारी सामने आई थी. इनमें से 24 मामला को गंभीर मानते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे, जबकि 45 मामलों का निस्तारण किया गया था.

उस बैठक में अधिकारियों ने जमीन की बाउंड्री कर कब्जा करने, राजस्व अभिलेखों में हेरफेर, किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन बेचने, खसरा नंबर बदलकर दूसरी जमीन दिखाने और वास्तविक रखे से अधिक जमीन बेचने जैसे मामलों का उल्लेख किया था.

जून 2025 में 58 लैंड फ्रॉड के मामले की समीक्षा हुई थी. इससे पहले जून 2025 में भी गढ़वाल मंडल के सात

पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रियों का दो दिवसीय चिंतन शिविर सेवा तीर्थ में संपन्न

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रियों का दो दिवसीय चिंतन शिविर सेवा तीर्थ में संपन्न हो गया. शिविर का मुख्य फोकस विकसित भारत / 2047 के लक्ष्य के साथ शासन सुधार, कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी डिलीवरी और मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल रहा. प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से कहा कि उन्हें केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि जमीन पर जाना है. इस चिंतन शिविर में सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की करीब 40 से 45 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, योजनाओं में जो कमियां हैं, उन्हें पहचानकर दूर करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए, इसकी भी समीक्षा की गई. सूत्रों की माने तो शिविर में सभी मंत्रियों को एक-एक पेज दिया गया. उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने साथी मंत्री से



क्या सीखा और उन्होंने खुद क्या सिखाया. इसका उद्देश्य अनुभवों का आदान-प्रदान बढ़ाना और अच्छी प्रथाओं को अपनाना था. सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे अपने मंत्रालय के अधिकारियों से नियमित रूप से मिलें, उन्होंने कहा कि कुछ मंत्री केवल सचिव से बात करते हैं, जबकि विभाग के अन्य अधिकारियों से संवाद नहीं रखते.

उनका कहना था कि योजनाओं के क्रियान्वयन की सही तस्वीर तभी साफ होती है, जब मंत्री पूरे प्रशासनिक ढांचे से जुड़े रहें. दो दिवसीय इस चिंतन शिविर के पहले दिन मंत्रियों को अलग-अलग समूहों में बांटा गया. प्रधानमंत्री स्वयं प्रत्येक टेबल पर जाकर चर्चा में शामिल हुए. गवर्नेंस, जन विश्वास, योजनाओं की समयबद्ध डिलीवरी, मंत्रालयों के बीच समन्वय और शिकायत

निवारण जैसे विषयों पर मथन हुआ. अगले चरण की चर्चा 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को भी प्रस्तावित है. इस चिंतन शिविर का मकसद समीक्षा के साथ अगली प्राथमिकताएं तय करना और योजनाओं को जमीनी स्तर पर और प्रभावी बनाना रहा. प्रधानमंत्री का संदेश साफ था. कृलाभाभी तक योजना पहुंचे, कमियां दूर हों और मंत्री मैदान में सक्रिय दिखें.

राहुल गांधी का पीएम मोदी और अमित शाह पर अब तक का सबसे तीखा हमला, ब्र से मांगा इस्तीफा



नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 'देशद्रोही' बताया, क्योंकि उन्होंने भारत के वोट को 'बर्बाद' किया है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के तुरंत इस्तीफे की मांग की. बता दें कि बुधवार को आई एक वीडियो रिपोर्ट से पता चला कि 10 नहीनों के अंदर, दो चुनाव आयुक्तों — विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू — ने प् और चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए दूसरे कदमों से जुड़े मामलों पर 14 बार आपत्तियां जताई थीं. राहुल गांधी ने गुरुवार को यहां

इतिरा बदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार पर निशाना साधा. कहा कि यह संविधान और देश के कानूनी ढांचे पर हमला है. लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि मोदी और शाह ने देश के साथ जो किया है, उसकी जांच की जाएगी. कुमार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ब्र ने जो किया है, वह भारतीय राष्ट्र के खिलाफ एक काम है. गांधी ने कहा कि कुमार को उनका सुझाव है कि उन्हें सरकारी गवाह बन जाना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रवाद का काम होगा. राहुल गांधी ने कहा, "यह संविधान और देश के कानूनी ढांचे पर

हमला है. आपको यह सुनिश्चित करना था कि वोट सुरक्षित रहे. हमारे पास इसे निश्चित रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त जानकारी है. इसके नतीजे होंगे. हम लोकतंत्र को बर्बाद होते हुए देखकर चुप नहीं बैठेंगे." गांधी ने कहा, "पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह, दोनों की जांच होगी कि क्या किया जा रहा है. वे इस साजिश में सबसे ऊपर हैं और उन्होंने देश के साथ जो किया है, उसके लिए उनकी जांच की जाएगी. "राहुल गांधी ने कुछ वीडियो दिखाए और लोगों से मोदी और शाह के लहजे को सुनने के लिए कहा.

गोवा में विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दी सफाई, प् को लेकर जानें क्या कहा

गोवा में विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सत्ताधारी बीजेपी पर आरोप लगाया कि वे वोटर लिस्ट के प् के जरिए आगामी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. विपक्ष ने आरोप लगाते हुए इस प्रक्रिया को वापस लेने की मांग की. हालांकि विपक्ष के इन आरोपों पर अब चुनाव आयोग ने सफाई दी है. चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा, "फरवरी 2026 में जारी अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए 97 नामलों के लिए, उन्हें घर-घर जाकर फॉर्म 6 भरवाने की प्रक्रिया अलग से पूरी की. इनमें से कई लोगों का नाम सूची में शामिल किया जा चुका है. जबकि बाकी मामलों पर अभी काम चल रहा है. यह फिर से दोहराया जाता है कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम नहीं



छूटेगा।" गोवा में विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग का बयान। पहम वनतबम : तथ्यतः प् गोवा में विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग का बयान। चुनाव आयोग बीजेपी का एक अंग बन गया है. कांग्रेस दरअसल, विपक्षी बलों ने उन रिपोर्टों का जिक्र किया था, जिनमें चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने प् के तहत गोवा समेत कई जगहों पर नाम हटाने से जुड़े मुद्दों पर

चिंता जताई थी। पार्टियों का कहना था कि यह चुनाव में गड़बड़ी करने जैसा है। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुनील कवथकर ने पणजी में कहा कि बीजेपी प् के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि गोवा जैसे राज्यों में पार्टी का सत्ता में लौटना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, "सही वोटों के नाम हटाना चुनाव में गड़बड़ी करने जैसा है। भारत का चुनाव आयोग बीजेपी का एक अंग बन गया है, जिसका इस्तेमाल वे चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं।" कांग्रेस नेता ने मांग की कि प् प्रक्रिया को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा, "पूरे देश में कांग्रेस को जो समर्थन मिल रहा है, उससे बीजेपी घबरा गई है, इसीलिए वे इस तरह के हथकंडों से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे

तेलंगाना सरकार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB अमीर हुसैन, क्राइम ब्यूरो चीफ

तेलंगाना राज्य, हैदराबाद में कचरा कार्यालय के तहत पुलिस कंप्यूटर सर्विस के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (वेब) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में तलाशी अभियान जारी इससे पहले, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एबी), सिटी रेंज-ए, हैदराबाद ने श्री सकीरेड्डी भीम रेड्डी (वेब, पुलिस कंप्यूटर सर्विस, कचरा कार्यालय, तेलंगाना राज्य, हैदराबाद) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 13(1)(ड) और धारा 13(2) के तहत बा.छप. 21एल-ए-ए-2026 (दिनांक 27.06.2026) के रूप में दर्ज किया गया था। पहले की तलाशी के क्रम में और एम और एम मामलों के माननीय प्रधान विशेष न्यायाधीश, हैदराबाद द्वारा जारी सर्च वारंट के आधार पर, आज यानी 24.09.2026 को हैदराबाद और जहीराबाद इलाकों में 10 अलग-अलग जगहों पर तलाशी ली गई। इन जगहों में उन संदिग्ध बेनामी लोगों के घर भी शामिल थे, जिन पर आरा. पी अधिकारी के साथ वित्तीय और अन्य लेन-देन का आरोप है। तलाशी के दौरान, संदिग्ध बेनामी संपत्तियों से जुड़े सबूत के तौर पर कई दस्तावेज और अन्य चीजें संदिग्ध बेनामी लोगों के घरों से जब्त की गईं। इसके अलावा, श्री बोम्मा वेंकटेश के घर पर 1.35 करोड़ रुपये नकद मिले। साथ ही, विदेशी मुद्रा और लगभग 14 लीटर विदेशी शराब भी मिली। विदेशी शराब के बारे में जरूरी कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग (नबपेम कमवतजउमदज) को सूचना दी गई है, और संबंधित आबकारी अधिकारियों द्वारा कानून के अनुसार मामला दर्ज किए जाने की संभावना है।



मामले की जांच चल रही है।

सेल फोन नंबर-1064 (टोल-फ्री नंबर) यदि कोई सरकारी कर्मचारी रिश्तत की मांग करता है, तो जनता से अनुरोध है कि वे कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए एबी के टोल-फ्री नंबर 1064 पर संपर्क करें। एबी तेलंगाना से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर (9440446106), थ्वम्सइव

(जमसंदहद एबी) और गूगल का जपजजमत (जमसंदहद एबी) के जरिए भी संपर्क किया जा सकता है। एबी तेलंगाना से संपर्क करने के लिए सभी सरकारी दफ्तरों और प्रमुख सार्वजनिक जगहों पर एबी का फ्लैग कोड लगाया गया है। पीडिटीशिकायतकर्ता का नाम और जानकारी गुप्त रखी जाएगी। 24.09.26, एटी-कराण ब्यूरो,

नामपल्ली, हैदराबाद के सीनियर सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (कै.) के सेक्रेटरी ने चंचलगुडा जेल का दौरा किया



अमीर हुसैन, क्राइम ब्यूरो चीफ



हैदराबाद, 24 सितंबर: नामपल्ली (हैदराबाद) के सेशन डिप्टी जज ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (कै.) की सेक्रेटरी सुश्री ए. श्रीदेवी ने चंचलगुडा में पुरुषों की जेल, लीगल एंड क्लिनिक, नशा-मुक्ति केंद्र और महिलाओं की जेल का दौरा और निरीक्षण किया। दौरे के दौरान, उन्होंने कैदियों



को दी जा रही कानूनी मदद और मुफ्त कानूनी सेवाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह पक्का करें कि जिन कैदियों को कानूनी मदद की जरूरत है, उन्हें डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जरिए मुफ्त कानूनी सेवाएँ मिलें। लीगल एंड क्लिनिक का निरीक्षण करने के बाद, उन्होंने सलाह दी कि कानूनी सेवाएँ इस तरह से उपलब्ध कराई जाएँ कि कैदी अपनी कानूनी समस्याओं को खुलकर बता सकें। उन्होंने नशा-मुक्ति केंद्र में इलाज करा रहे लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया और

अधिकारियों के साथ जरूरी मदद और सहयोग पर चर्चा की। इसके बाद, उन्होंने चंचलगुडा महिला जेल का दौरा किया और महिला कैदियों को दी जा रही कानूनी सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल और कल्याणकारी उपायों के बारे में जानकारी ली। सुश्री ए. श्रीदेवी ने इस बात पर जोर दिया कि यह पक्का किया जाए कि कानूनी मदद की जरूरत वाले हर कैदी को उचित सहायता मिले। जेल सुपरिंटेंडेंट श्री शिवकुमार गौड़ और सुश्री अमरावती के साथ-साथ जेल के अन्य अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

साइबर ठगी के शिकार पीड़ितों पर दोहरी मार! शिकायत के लिए रिश्तत का दबाव, पुलिस और बैंकिंग संस्थानों से सही सहयोग की कमी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों और बैंकिंग संस्थानों से साइबर क्राइम से लड़ने के लिए मिलकर काम करने को कहा था। उनके इस बात को कहने के महीने बाद गुरुवार को 'साइबर क्राइम क्विडिक्टम परसेप्टिक्स एंड सिस्टमिक रिस्पॉन्स' पर भारत में पुलिस व्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट (एच) 2026 से पता चलता कि पुलिस और बैंकिंग संस्थानों से सही सहयोग की कमी ने स्थिति को और बिगाड़ कर रखा दिया है। कॉमन कॉज और लोकनीति-सीएसडीएस की मिलकर की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि साइबर क्राइम के मामलों में आमतौर पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। नई दिल्ली में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन 15 पीड़ितों ने पुलिस से ऑनलाइन या खुद जाकर शिकायत की थी उनमें से छह मामलों में एफआईआर दर्ज की गईं, इनमें से दो ऑटोमेटिक एफआईआर थीं, वहीं कम से कम दो अन्य मामलों में, पीड़ितों ने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए प्रभावशाली लोगों से संपर्क किया। ब्लडमैटवतपउम अपवजपउ जतनहहसम जब हमज खवसपवम, ईवा नचघवतज: थमदके थम 2026 भारत में पुलिस व्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट (एच) 2026 (एच टीज) कॉमन कॉज के डायरेक्टर विपुल



मुद्गल ने कहा कि इस अध्ययन का मकसद साइबर क्राइम के बारे में लोगों की सोच और अनुभव और उनसे निपटने के लिए सिस्टम की तैयारी को समझना है। यह अध्ययन 18 भारतीय राज्यों में 8,306 से ज्यादा लोगों के सर्वेक्षण पर आधारित है। इसका मकसद भारत में साइबर क्राइम के तेजी से बदलते प्रकृति और उनसे निपटने के लिए बने सिस्टम की जांच करना है। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय साइबर अपराध के पीड़ितों और जानकारी के ज्यादात यह महसूस किया कि बैंकों ने जिम्मेदारी लेने या रिकवरी प्रक्रिया में पीड़ित की मदद करने से मना कर दिया। एक मामले को छोड़कर वित्तीय धोखाधड़ी (फाइनेंशियल फ्रॉड) के

पीड़ितों के साथ बाकी सभी इंटरव्यू में बैंकों ने कहा कि पीड़ितों ने फ्रॉड करने वाले के साथ 'सहयोग' किया। पुलिस और बैंकिंग संस्थानों से सही सहयोग की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। साइबर क्राइम के मामलों से निपटने में पुलिस को दी गई औसत रेटिंग पांच में से 2.4 थी। बैंकों के साथ अपने अनुभव को रेट करने वाले छह पीड़ितों में से कुल रेटिंग पांच में से एक खराब थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस से शिकायत करने वाले पांच में से दो (42 प्रतिशत) पीड़ितों को शिकायत दर्ज करने का प्रक्रिया मुश्किल लगा, 17 प्रतिशत को यह बहुत मुश्किल लगा और 25 प्रतिशत ने कहा कि यह कुछ हद तक मुश्किल था। जिन लोगों ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाई उनमें से एक चौथाई से ज्यादा (27 प्रतिशत) ने पुलिस को

मेडिकल कॉलेजों में फर्जी प्रमाण पत्रों से दाखिले का नया मामला, अधिवक्ता समेत चार अरेस्ट



रुद्रपुर: देहरादून के बाद उधम सिंह नगर जिले में भी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए फर्जी पत्रे और कूटचित दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र बनवाने का मामला सामने आया है। मामला बाजपुर तहसील क्षेत्र का है। उधम सिंह नगर जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई जांच में संबंधित अभ्यर्थियों के बताए पते पर निवास नहीं करने की पुष्टि हुई। प्रशासन ने प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए एक अधिवक्ता समेत चार लोगों के खिलाफ बाजपुर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। साथ ही पूर्व में जारी प्रमाण पत्रों का भी दोबारा सत्यापन शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देश पर 23 सितंबर 2026 को विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से सत्यापन के लिए प्राप्त प्रमाण पत्रों की जांच कराई गई। बाजपुर तहसील क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्रों के भौतिक सत्यापन के लिए उप जिलाधिकारी ब्रज सिंह के निर्देश पर राजस्व उप निरीक्षक और राजस्व टीम ने स्थलीय जांच की जांच में हुआ खुलासा: प्रशासन के अनुसार स्थलीय सत्यापन के दौरान संबंधित अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों में दर्ज पते पर निवास नहीं पाए गए। इसके बाद प्रमाण पत्रों के साथ लगाए गए दस्तावेजों की संबंधित विभागों से जांच कराई गई। जांच में कथित तौर पर यह सामने आया कि कुछ अभ्यर्थियों ने स्थानीय लोगों की सहायता से गलत पते और कूटचित साक्ष्यों के आधार पर प्रमाण पत्र बनवाए थे। परिजनों से की गई पुछताछ: इन प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए किए जाने की बात सामने आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने संबंधित अभ्यर्थियों के परिजनों को तहसील में बुलाकर पुछताछ की। अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर, उप जिलाधिकारी बाजपुर, तहसीलदार बाजपुर और राजस्व टीम की मौजूदगी में परिजनों व अन्य संबंधित लोगों के लिखित बयान भी दर्ज किए गए। पुछताछ और दस्तावेजों की जांच के बाद प्रशासन ने फर्जी पाए गए प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया। प्रशासन की ओर से बाजपुर कोतवाली में शाम बहारी भोजवाल पुत्र गेदन लाल निवासी दौलतपुर रोड बरखेड़ा तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश निवासी माधुर पुत्र बालजीत निवासी तुला शेरपुर इज्जतनगर जिला बरेली उत्तर प्रदेश अर्चना पत्नी आशीष भारद्वाज निवासी मुखियाकला, बाजपुर, उधम सिंह नगर रोहित पुत्र राजेंद्र निवासी हरलालपुर बाजपुर बाजपुर के एक अज्ञात अधिवक्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुराने प्रमाण-पत्रों की भी होगी जांच: पुलिस

चसपदमत: क्यों अपनी ही पार्टी के नीरज कुमार को हराना चाहते हैं अनंत सिंह? 11 साल के अदावत की इनसाइड स्टोरी समझिए



पटना: बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की आठ सीटों पर चुनाव होना है। कई सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने फिलहाल आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। इसके बावजूद, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। यहां जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के दो दिग्गज नेताओं के बयानों ने सियासी सरगमी बढ़ा दी है। पुराने साथियों में अदावत जदयू नेता नीरज कुमार चौधरी बार पटना स्नातक क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरी तरफ, मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह ने पार्टी में रहते हुए भी एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी का खुलकर समर्थन कर दिया है। वे सार्वजनिक मंचों से नीरज कुमार को हराने का दावा कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच यह अदावत कई वर्षों पुरानी है। अब चुनावी बहस में एके-47 से लेकर लालू प्रसाद तक का जिक्र होने लगा है। 11-47 का गंभीर आरोप विधायक अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि नीरज कुमार की वजह से ही उन्हें पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाना पड़ा था। उन्होंने दावा किया कि उनके घर से जो एके-47 बरामद हुई थी, वह नीरज कुमार द्वारा ही प्लांट कराई गई थी। इसी साजिश के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। हालांकि, नीरज कुमार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कोर्ट में सबूत पेश करने की चुनौती दी है। बदले की सियासी लड़ाई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अतीत में नीरज कुमार ने भी कई मौकों पर अनंत सिंह का कड़ा विरोध किया था। अब अनंत सिंह उसी का पुराना बदला ले रहे हैं। हालांकि, जानकारों का कहना है कि वे अपनी ही पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ बहुत आगे तक नहीं जा सकेंगे। बहरहाल, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चुनावी जंग ने सूखे के राजनीतिक गलियारों में भारी हलचल पैदा कर दी है। वोटों का पुराना गणित दोनों नेताओं के बीच का यह विवाद करीब डेढ़ दशक पुराना है, जो साल 2015 के बाद से और ज्यादा बढ़ गया। इससे पहले वर्ष 2005 और 2010 के चुनावों में नीरज कुमार ने अनंत सिंह के लिए प्रचार किया था, लेकिन 2015 में समीकरण बदले और अनंत सिंह बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े, उस समय जेल में रहते हुए भी उन्होंने नीरज कुमार को 18,348 वोटों के अंतर से करारी शिकस्त दी थी। महावीर मंदिर में बिबेक का चौलेंज अनंत सिंह का दावा है कि नीरज कुमार ने उन्हें हराने की चार बार कोशिश की, लेकिन जनता के समर्थन के कारण वे कभी सफल नहीं हो सके। उन्होंने नीरज कुमार पर पहली बार विधान परिषद का टिकट पाने के लिए पैर पमाहावीर मंदिर में बिबेक का चौलेंज अनंत सिंह का दावा है कि नीरज कुमार ने उन्हें हराने की चार बार कोशिश की, लेकिन जनता के समर्थन के कारण कड़ने का भी आरोप लगाया, अनंत सिंह ने सीधी चुनौती देते हुए कहा कि नीरज कुमार पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में आकर उनके साथ सार्वजनिक बिबेक करें, ताकि सब सामने आ सके। 'मेरे घर में एक-47 नीरज ने ही प्लांट करवाया था इसके कारण मुझे जेल जाना पड़ा था, नीरज ने हमारा पैर पकड़ा, हमने नीतीश कुमार और ललन सिंह का पैर पकड़ा, तब नीरज को पहली बार विधान परिषद का टिकट मिला, महावीर मंदिर में बिबेक करें, हम बताएंगे कि नीरज ने मेरा कितना विरोध किया, कितनी गांठी दी, नीरज ही बताएंगे कि मैंने उनका कब अहित किया।'— अनंत सिंह, मोकामा विधायक

विजयवाड़ा मेयर की सीट के लिए पवन कल्याण पर दबाव..?

जन सेना का निशाना बेजवाड़ा मेयर की सीट अलायंस में मेयर की सीट किसे मिलेगी? चर्चा जारी
अगर मेयर की सीट जन सेना को मिलती है.. तो क्या पेनुगोंडा के पास मौका है?



विजयवाड़ा: बेजवाड़ा शहर की पॉलिटिक्स में मेयर की सीट को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। जहां पॉलिटिकल गलियारों में इस बात की चर्चा है कि आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन में जन सेना विजयवाड़ा मेयर का पद मांग सकती है.. वहीं मेयर कैंडिडेट के तौर पर पेनुगोंडा सुब्बारायडू का नाम सामने आना दिलचस्प हो गया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि अलायंस में किस पार्टी को मेयर का पद मिलेगा.. लेकिन पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा है कि अगर जन सेना को मौका मिलता है तो सुब्बारायडू के नाम पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, आखिरी फंसला पार्टी हाईकमान और अलायंस कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करता है। पेनुगोंडा सुब्बारायडू का पॉलिटिक्स से पहले लंबा करियर और सोशल सर्विस का बैकग्राउंड रहा है। एक जाने-माने चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर उनके पास चार दशकों से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने फाइनेंस, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट गवर्नंस और फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े मामलों में काम किया है। उन्होंने साउथ इंडिया रीजनल काउंसिल की कमेटियों में भी काम किया है। उन्होंने रीजनल

डायरेक्ट टैक्स एडवाइजरी कमेटी के मंबर के तौर पर भी काम किया है। इस मामले में, उनका गुप्त मेयर पद के लिए फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में उनके अनुभव को एक अच्छा फीचर बता रहा है। सुब्बारायडू का सोशल स्टेटस भी उनकी एक और ताकत लगता है। उन्होंने आर्य वैश्य महासभा में अहम जिम्मेदारियां निभाईं।



उन्होंने 2018 से 2020 तक स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया। बाद में वे ऑनरेरी प्रेसिडेंट बने रहे। उन्होंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन, वासावी सत्र कॉम्प्लेक्स के आर्बिट्रेटर, चैतन्य तथा वनम के ऑनरेरी प्रेसिडेंट और वासावी कन्याका परमेश्वरी मंदिर के ऑनरेरी प्रेसिडेंट के तौर पर कई जिम्मेदारियां निभाईं हैं। उन्होंने विजयवाड़ा क्लब के पूर्व ट्रेजरर के तौर पर भी काम किया है। इससे यह चर्चा है कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के साथ-साथ सोशल सर्कल में उनके कॉन्टैक्ट पॉलिटिकल तौर पर भी काम आएंगे। पेनुगोंडा सुब्बारायडू का लायंस क्लब से पुराना नाता है। वह 38 साल से ज्यादा समय से लायंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कई जिम्मेदारियां निभाईं हैं। उन्होंने विजयवाड़ा ईस्ट लायंस आई हॉस्पिटल के ऑनरेरी चेयरमैन के तौर पर काम किया। वह गरीब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मदद करते हैं। वह मुशीराबाद आर्य वैश्य हॉस्टल के डोनर-चेयरमैन और विजयवाड़ा आर्य वैश्य हॉस्टल के डोनर-कन्वीनर के तौर पर काम करते हैं। ऐसी राय है कि यह सर्विस बैकग्राउंड उनकी मेयर

कैंडिडेट बनने की दौड़ में एक और ताकत बनेगा। पॉलिटिकली, पेनुगोंडा सुब्बारायडू का सफर जन सेना से शुरू हुआ। पवन कल्याण के सर्विस वाले खैये से प्रभावित होकर, वह 10 जुलाई, 2025 को जन सेना में शामिल हो गए। उसके बाद, पार्टी के प्रोग्राम में एक्टिव रूप से हिस्सा लेते हुए, वह पार्टी के विल्डिंग लीडर्स के लिए सेंट्रल कमेटी ऑफ

इन्फॉर्मेशन के मंबर के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह पार्टी से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने और उसे कोड़ करने वाली पांच मंबर वाली कमेटी के मंबर में से एक हैं। हालांकि वह पॉलिटिकली नए लगते हैं, लेकिन पार्टी प्रोग्राम में ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में अपने लंबे अनुभव का इस्तेमाल करने का मौका उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, असली सवाल यह है कि क्या विजयवाड़ा मेयर की सीट जन सेना को मिलेगी। लोकल बॉडी इलेक्शन में कोएलेशन पार्टियों के बीच रिप्रेजेंटेशन और सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस पर अभी भी क्लेरिटी की जरूरत है। अगर मेयर का पद जन सेना को मिलता है, तो पेनुगोंडा सुब्बारायडू के नाम पर विचार हो सकता है, इस चर्चा के बीच कि पार्टी को सोशल कॉन्टैक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल अनुभव और फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव समझ वाले कैंडिडेट की जरूरत हो सकती है। हालांकि, मेयर कैंडिडेट के तौर पर उनके नाम पर अभी ऑफिशियल फंसला होना बाकी है। इसके साथ ही, जन सेना ने बेजवाड़ा मेयर सीट पर अपना पल्ला झाड़ लिया है। क्या पेनुगोंडा सुब्बारायडू को ग्रीन सिग्नल मिलेगा? यह अब विजयवाड़ा के पॉलिटिकल सर्कल में एक दिलचस्प चर्चा बन गई है।

इस्तीफा देकर उपचुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से मुआवजा वसूलने का आदेश नहीं दिया जा सकता: हाई कोर्ट

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह भारत निर्वाचन आयोग (एन) को उन उम्मीदवारों से मुआवजा वसूलने का आदेश नहीं दे सकता जो इस्तीफा देकर दोबारा उपचुनाव लड़ते हैं। अप्रैल में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद मद्रास हाई कोर्ट (इंडियन कोर्ट), तारापुरम, अम्बासमुद्रम (इंडियन कोर्ट), पेरुदुरई (छातनदकनतप), करूर और विरालीमलाई (टपतसपउंसप) निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए छह एनकाउंड विधायकों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और जट्टा में शामिल हो गए। हाई कोर्ट ने अम्बासमुद्रम, पेरुदुरई, करूर, विरालीमलाई और त्रिची पूर्व सीटों पर उपचुनाव की घोषणा पर रोक लगा दी है, जहां चुनाव मामले लंबित हैं, जबकि चुनाव आयोग ने मद्रास हाई कोर्ट और तारापुरम निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। चेन्नई के सैदापेट के वकील सुवन ने मद्रास हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें चुनाव आयोग को यह आदेश देने की मांग की गई है कि वह उम्मीदवारों द्वारा उपचुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय चुनाव खर्च जमा करने की एक उचित प्रक्रिया तैयार करे। याचिका में कहा गया है कि जहां विधायकों के अपने राजनीतिक कारणों से इस्तीफा देने के कारण सरकारी खर्च पर उपचुनाव कराने पड़ते हैं, वहां उन्हें इन खर्चों के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए उचित प्रक्रियाएं तैयार की जानी चाहिए। इसके अलावा, याचिका में यह अनुरोध किया गया है कि एक ऐसा कानून बनाने के लिए अध्ययन किया जाए जो उन लोगों को चुनाव नतीजों की घोषणा के कुछ ही समय बाद राजनीतिक कारणों से अपने पद से इस्तीफा देने और जनता के जनादेश की उम्मेदारी करने पर, एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर सके। याचिका में अनुरोध किया गया है कि मामला सुलझने तक मद्रास हाई कोर्ट और तारापुरम निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनावों पर रोक लगाई जाए, और चुनाव आयोग को पूर्व विधायकों मरागाथम कुमारवेल (इंटरहंजीउ ज्ञानउतमस) और सत्यनारायण (जीपलंडीउ) के नामांकन पत्र स्वीकार करने से रोक दिया जाए, जिन्हें इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसी तरह, याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि चुनाव आयोग को त्रिची पूर्व, करूर, विरालीमलाई, पेरुदुरई, अम्बासमुद्रम, मद्रास हाई कोर्ट और तारापुरम निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव कराने में हुए खर्च पर एक रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया जाए। यह मामला वीफ जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुण मुरुगन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिगरावेलन ने कहा, "उम्मीदवारों ने लोगों के जनादेश को खारिज कर दिया और दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इसलिए, मरागाथम कुमारवेल और सत्यनारायण दोनों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। एक पार्टी से चुने जाना और फिर उसे छोड़कर दूसरी पार्टी में चुनाव लड़ना दल-बदल कानून से बचना है।" चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा, "याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है। लोकतांत्रिक तरीके से इस्तीफा देने वाले किसी सदस्य के दोबारा चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है।" कोर्ट ने कहा, "इस मामले में किस आधार पर आदेश जारी किया जा सकता है? इस्तीफा देने और फिर से चुनाव लड़ने वालों से मुआवजा वसूलने का अभी तक कोई कानून नहीं है। किसी भी कानून के अभाव में, अदालत मुआवजा वसूलने का आदेश कैसे जारी कर सकती है? अदालत कानून नहीं बना सकती। अदालत सिर्फ दस्तावेजों के आधार पर ही यह जांच कर सकती है कि क्या सही है और क्या गलत।" पीठ ने कहा, "चुनाव आयोग को उम्मीदवारों से चुनाव खर्च वसूलने और उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट चुनाव आयोग को उम्मीदवारों से चुनाव खर्च वसूलने के लिए कानून बनाने का आदेश कैसे दे सकता है?"

मीडिया रिपोर्ट में दो चुनाव आयुक्तों द्वारा 14 बार आपत्ति जताने के दावे के बाद राहुल गांधी ने सरकार और एन को घेरा।

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 'देशद्रोही' बताया, क्योंकि उन्होंने भारत के वोट को 'बर्बाद' किया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के तुरंत इस्तीफे की मांग की।



बता दें कि बुधवार को आई एक मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि 10 महीनों के अंदर, दो चुनाव आयुक्तों - विवेक जोशी और सुखवीर सिंह सधू - ने 14 बार आपत्तियां जताई थीं। राहुल गांधी ने गुरुवार को बड़ा इंडिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि यह संविधान और देश के कानूनी ढांचे पर हमला है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि मोदी और शाह ने देश के साथ जो किया है, उसकी जांच की जाएगी। कुमार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि एन ने जो किया है, वह भारतीय राष्ट्र के खिलाफ एक काम है। गांधी ने कहा कि कुमार को उनका सुझाव है कि उन्हें सरकारी गवाह बन जाना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रवाद का काम होगा। राहुल गांधी ने कहा, "यह संविधान और देश के कानूनी ढांचे पर हमला है। आपको यह सुनिश्चित करना था कि वोट सुरक्षित रहे। हमारे पास इसे निश्चित रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त जानकारी है। इसके नतीजे होंगे। हम लोकतंत्र को बर्बाद होते हुए देखकर चुप नहीं बैठेंगे।" गांधी ने कहा, "पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह, दोनों की जांच होगी कि क्या किया जा रहा है। वे इस साजिश में सबसे ऊपर हैं और उन्होंने देश के साथ जो किया है, उसके लिए उनकी जांच की जाएगी।" राहुल गांधी ने कुछ वीडियो दिखाए और लोगों से मोदी और शाह के लहजे को सुनने के लिए कहा। वीडियो में शाह को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उम्र 30 साल तक सत्ता में रहेगी और प्रधानमंत्री को 'अबकी बार 400 पार' का नारा लगाते हुए सुना जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतांत्रिक माहौल में काम करने वाला कोई भी राजनीतिक नेता ऐसे बयान नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि भारत में 'एंटी-इंकम्बेंसी' नाम की एक बुनियादी ताकत होती है जो विरोध करना शुरू कर देती है और यह किसी को नहीं बख्शाती। राहुल गांधी ने कहा- भारत में एंटी-इंकम्बेंसी हर सरकार को प्रभावित करती है, लेकिन मोदी, शाह और बीजेपी पर यह गायब हो जाती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश युद्ध जीता था और उनकी अपार लोकप्रियता थी, फिर भी एक-दो साल के अंदर ही भारी एंटी-इंकम्बेंसी आ गई थी।

विजयनगरम में ड्वाकरा महिलाओं के लिए महारदास - मंत्री कौंडापल्ली श्रीनिवास ने 13.29 एकड़ जमीन देने के लिए बड चंद्रबाबू को धन्यवाद दिया

विजयनगरम, 24 सितंबर:

राज्य सरकार ने विजयनगरम जिले की 4.36 लाख ड्वाकरा बहनों की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, और वह करोड़ों रुपये की 13.29 एकड़ जमीन मुफ्त में देने के लिए मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू के दिल से शुकगुजार हैं, ऐसा डेडम, म्द, छन सर्विसेज और एम्पावरमेंट मंत्री कौंडापल्ली श्रीनिवास ने कहा। मंत्री ने इस बारे में एक प्रेस रिलीज जारी की। राज्य कैबिनेट ने विजयनगरम मंडल के वैष्णोपाल, पुरम विट-2 गाँव के सर्वे नंबर 536ए में करोड़ों रुपये की 13.29 एकड़ सरकारी जमीन डिस्ट्रिक्ट रूल डेवलपमेंट अथॉरिटी (क्व) को देने को मंजूरी दे दी है। मंत्री कौंडापल्ली श्रीनिवास ने कहा कि यह जमीन, जो विजयनगरम शहर के पास है और जिसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों रुपये है, गरीबी हटाने और महिला सशक्तिकरण के मकसद से मुफ्त में दी जा रही है, यह मुख्यमंत्री के महिलाओं के प्रति भेदभाव का सबूत है।

4.36 लाख महिलाओं को रोजगार देने के मकसद से इटीग्रेटेड कैंपस मंत्री ने कहा कि उनकी खास पडल से बने इस बड़े प्रोजेक्ट के जरिए, जिले के 1,023 गांव फंडेशन की महिलाओं को एंटरप्रेन्योर के तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इन 13.29 एकड़ में 5 इटीग्रेटेड सेंटर बनाए जाएंगे।
- बाजरा प्रोसेसिंग यूनिट - 4 एकड़: रागी, ज्वार, साजा और कोरा जैसे छोटे अनाजों की वैल्यू-एडेड



प्रोसेसिंग से महिलाओं के लिए एक पक्की इनकम।
- बायोगैस प्लांट - 3 एकड़: कचरे से प्यूल और ऑर्गेनिक खाद बनाना।
- स्किल डेवलपमेंट सेंटर - 2 एकड़: गांव के

युवाओं और महिलाओं को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग।
- ड्वाकरा ट्रेनिंग एंड नौलेज सेंटर - 2.29 एकड़: लीडरशिप और बिजनेस स्क

धनबाद की चिप को राष्ट्रीय मंच पर मिला सम्मान, पीएम ने किया हैंडओवर



धनबाद: भारत में स्वदेशी सेमीकंडक्टर तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में आईआईटी (आईएसएम) धनबाद ने एक और उपलब्धि हासिल की है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन समारोह के दौरान चिप हैंडओवर सेरेमनी में संस्थान की रिसर्च टीम द्वारा विकसित चिप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया। इस दौरान आईआईटी (आईएसएम) धनबाद की ओर से रिसर्च स्कॉलर राहुल रंजन ने चिप और स्मृति चिह्न प्राप्त किया। यह चिप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर प्रो. राजीव कुमार रंजन के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। देशभर के 20 संस्थानों के छात्रों की ओर से विकसित चिप्स को इस विशेष समारोह में सम्मानित किया गया।

आईआईटी (आईएसएम) धनबाद की यह चिप डपदपेजतल वा म्ममवजतवदपवे दक पवितरंजपवद ज्मबीदवसवहल (डमपजल) द्वारा वित पोषित प्रोजेक्ट 'न्सजत-स्वु च्चुमत 'पेजपअम'उंतज ल्स' के तहत विक. सित की गई है। चिप का निर्माण 'मउपववदकनवजवत र्द्वतजवतल (रू), मोहाली में किया गया है। यह डिजिटल एप्लीकेशन-स्पेसिफिक इंटिग्रेटेड सर्किट यानी 'चिप' है, जिसे 7670 कैमरा के जरिए रियल टाइम इमेज प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे स्मार्ट ग्लास विकसित करना है, जो आकार में कॉम्पैक्ट होने के साथ कम ऊर्जा की खपत करें। इस तकनीक का इस्तेमाल केवल स्मार्ट ग्लास तक सीमित नहीं है। इसकी आर्किटेक्चर और प्रोसेसिंग तकनीक को बायोमेडिकल इमेजिंग, असिस्टिव हेल्थकेयर डिवाइस, वियरेबल सेंसर और एज एआई सिस्टम जैसे क्षेत्रों में भी उपयोग किया जा सकता है। चिप को मिले राष्ट्रीय सम्मान पर प्रो. राजीव कुमार रंजन ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया जैसे बड़े मंच पर संस्थान की टीम द्वारा विकसित चिप को पहचान मिलना पूरे विभाग के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि इस तरह का मंच युवा शोधकर्ताओं को सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही, स्वदेशी चिप डिजाइन और निर्माण की दिशा में भारत की क्षमता को भी इससे मजबूती मिलेगी।

पैनल ऑडिटोरियम में छात्रों ने देखा लाइव कार्यक्रम। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन समारोह और चिप हैंडओवर सेरेमनी का लाइव प्रसारण आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के पैनल ऑडिटोरियम में भी किया गया। संस्थान के छात्रों और फैकल्टी सदस्यों ने कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। इस मौके पर संस्थान के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा, रजिस्ट्रार प्रबोध पांडेय, डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रो. सजय मंडल, एसोसिएट डीन (स्टूडेंट्स वेल बीइंग) प्रो. संजीव आनंद साहू, प्रो. राजीव कुमार रंजन सहित अन्य फैकल्टी और संस्थान के सदस्य मौजूद रहे। सेमीकॉन इंडिया 2026 में मिली यह पहचान आईआईटी (आईएसएम) धनबाद में चल रहे स्वदेशी सेमीकंडक्टर डिजाइन, लो-पावर चिप और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय मंच पर सामने लाती है।

हिमालयी जड़ी-बूटियों के संरक्षण के लिए बनेगा रोडमैप, संगंध खेती से जुड़े हैं करीब 47 हजार किसान



देहरादून: उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद जड़ी-बूटियों के बेहतर इस्तेमाल और किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए विभागीय स्तर से पहल शुरू हो गई है। प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हजारों की संख्या में वनस्पतियां मौजूद हैं, जिसमें से करीब 2,300 वनस्पतियां ऐसी हैं, जिनका इस्तेमाल सदियों से दवाओं के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको देखते हुए अब आयुष विभाग प्रदेश में मौजूद जड़ी बूटियों के बेहतर इस्तेमाल और किसानों को प्रमोट करने पर जोर दे रहा है। इसके लिए आयुष विभाग जल्द ही उद्यान विभाग जड़ी-बूटी केंद्र समेत अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही है। इसको लेकर आयुष विभाग की ओर से एक खाका तैयार किया गया है।

इस खाके को लेकर उद्यान विभाग जड़ी-बूटी केंद्र और अन्य संबंधित विभागों के साथ बैठक कर विस्तृत रोडमैप तैयार किया जाएगा। इस रोडमैप में मुख्य फोकस इस बात पर होगा कि प्रदेश के किसानों को विभाग कैसे प्रमोट कर रहा है और इस प्रक्रिया में आयुष विभाग की क्या भूमिका हो सकती है? जड़ी-बूटी और संगंध खेती से जुड़े हैं करीब 47 हजार किसान: उत्तराखंड प्राकृतिक रूप से जड़ी-बूटियों का भंडार है। राज्य में पहले से ही जड़ी-बूटी और संगंध खेती से जुड़कर करीब 47 हजार किसान काम कर रहे हैं। ऐसे में आयुष विभाग ने प्रदेश को आयुष प्रदेश बनाने की दिशा में 186 गांवों को जड़ी-बूटी ग्राम के रूप में चिह्नित किया है, जिनमें से 13 गांव आयुष ग्राम बनने के लिए तैयार हैं।

टॉप जम्बोवन तुलसी का पौधा (फाइनल फोटो) - लनो क्मयंतजउमदज) राज्य सरकार पहले ही जड़ी-बूटी और संगंध प्रजाति के पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी बढ़ा चुकी है। कुछ प्रजातियों पर सब्सिडी में ढाई से तीन गुना तक वृद्धि की गई है। अधिकतम अनुदान की सीमा एक लाख रुपये या दो हेक्टेयर क्षेत्रफल निर्धारित की गई है।

जपउनात

2012 में 17 साल की लड़की का बेरहमी से रेप और मर्डर: सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक के उज्जीरे में 2012 में 17 साल की नाबा, लिंग लड़की के रेप और मर्डर की जांच ने उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया है, अदालत ने इस जांच को पीड़िता के साथ बहुत बड़ा अन्याय बताया। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि गलत तरीके से मुकदमा चलाने पर मुआवजा दिया जा सकता है लेकिन जिस लड़की का बेरहमी से रेप और मर्डर हुआ है और उसे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। यह कहते हुए कि समाज को पीड़िता को निराश नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से जांच का आदेश दिया और अधिकारियों को असली दोषियों को सजा दिलाने का निर्देश दिया। जस्टिस संजय कुमार और सजीव सचदेवा की बेंच ने कहा कि अक्टूबर 2012 में बेलथांगडी पुलिस द्वारा मूल रूप से दर्ज की गई शिकायत और उसके बाद दर्ज की गई एफआईआर की नए सिरे से जांच की जानी चाहिए। बेंच ने कहा कि कर्नाटक सरकार को एक विशेष जांच दल (एज) बनानी चाहिए जिसमें कुशल जांचकर्ता हों। ऐसे जांचकर्ता जो आधुनिक जांच तकनीक के इस्तेमाल से अच्छी तरह वाकिफ हों, और जिसका नेतृत्व राज्य का एक सीनियर पुलिस अधिकारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेलथांगडी पुलिस थाना, सीआईडी या सीबीआई की जांच टीम का कोई भी अधिकारी जो इस मामले से पहले से जुड़े थे वे लोग स्पेशल जांच दल का हिस्सा नहीं होंगे। बेंच ने आगे कहा, मामले पर नई जांच तीन महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी और पुलिस रिपोर्ट कानून के मुताबिक संबंधित कोर्ट में फाइल की जाएगी। उसके बाद मामला कानून के मुताबिक आगे बढ़ेगा। बेंच ने कहा कि ऐसे मामले में जहां 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ बेरहमी से रेप और मर्डर किया जाता है, जिस तरह से जांच आगे



बढ़ी है और जिस तरह से अलग-अलग जांच एजेंसियों ने जांच की और सबूत इकट्ठा किए और उनकी जांच की उससे कोर्ट की अंतरात्मा भी हिल गई है। बेंच ने कहा कि जिस व्यक्ति पर केस चला उसे जुर्म करने के कबिल नहीं पाया गया और जांच इस तरह से की गई जिससे पीड़िता के साथ अन्याय हुआ। बेंच ने कहा कि असली गुनहगारों के जांच में हेरफेर करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह की ढीली और गलत जांच उन जांच अधिकारियों को फायदा देती है जो अपना काम सही और मेहनत से करने में नाकाम रहे। बेंच ने कहा, "जिस व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया गया था, उसके साथ हुए अन्याय की हमेशा भरपाई की जा सकती है। लेकिन जिस पीड़िता का बेरहमी से रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई, उसके साथ हुए अन्याय की कमी भरपाई नहीं की जा सकती। बेंच ने कहा, "अगर समाज ऐसे जघन्य अपराध की पीड़िता को सही जांच करके और असली गुनहगारों को सजा दिलाकर न्याय नहीं देता है तो वह अपने कर्तव्य में नाकाम होगा।" आपराधिक मामले में कमी का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि खास हालात में अदालत आपराधिक न्याय (क्रिमिनल जस्टिस) की

गलती को रोकने के लिए और अगर जरूरी समझे तो नए सिरे से जांच का निर्देश दे सकता है। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक निष्पक्ष जांच, संविधान के आर्टिकल 21 के तहत गारंटी वाले संवैधानिक अधिकार का उतना ही हिस्सा है जितना कि एक निष्पक्ष सुनवाई, जिसके बिना सुनवाई स्वाभाविक रूप से निष्पक्ष नहीं होगा। बेंच ने कहा, "जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और सही होनी चाहिए क्योंकि यह कानून के शासन की अनिवार्य व बुनियादी शर्त है। जांच एजेंसी को दायी और पक्षपाती तरीके से जांच करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जहां कोर्ट के दखल न देने से आखिरकार न्याय नहीं होगा, वहां कोर्ट को दखल देना चाहिए।" डीएनए जांच करने वाले टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन के सहायक निदेशक के बयान पर ध्यान देते हुए बेंच ने कहा कि उनके बयान से पता चलता है कि अगर संदिग्ध लोग मिलते हैं, तो पीड़ित के कपड़ों से लिए गए डीएनए सैंपल का मिलान अभी भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इस तरह, ढाई कोर्ट का यह कहना कि यह शक है कि जो सबूत गोल्डन आवर में इकट्ठा नहीं किए जा सके, वे अभी भी मौजूद हैं और अगर दोबारा जांच की इजाजत दी भी गई तो भी कोई काम का मुकसद पूरा नहीं होगा। साफ तौर पर गलत है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता।" बेंच ने कहा कि जरूरी गवाह मौजूद हैं और दूसरे लोगों के बाल भी मौजूद हैं जिन्हें जरूरी चीज के तौर पर पेश किया गया है। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है, तो उसका ब्लड सैंपल लिखा जा सकता है और उसकी डीएनए जांच से तुलना की जा सकती है। बेंच ने कहा कि इस प्रचक्रम में न्याय के लिए यह जरूरी होगा कि नए सिरे से फिर से जांच (डीनोवोटीइन्वेस्टिगेशन) के सवाल पर कानून और उन हालात की जांच की

एमपीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव के नामांकन के पहले ही दिन चुनावी माहौल गरमा गया। एबीवीपी के तीन प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हुए।

मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव के नामांकन के पहले ही दिन चुनावी माहौल गरमा गया। नामांकन पत्रों की प्रारंभिक जांच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के तीन प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों में खामियां मिलीं, जिसके बाद नामा. कन पत्र को निरस्त करने की मांग को लेकर एनएसयूआई समेत अन्य छात्र नेताओं ने कॉलेज परिसर और गेट पर जमकर हंगामा किया। मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में नामांकन के पहले ही दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) को बड़ा झटका लगा है। नामांकन पत्रों की प्रारंभिक जांच में एबीवीपी की ओर से उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर दाखिल किए गए तीन नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए। इनमें उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी की उम्र निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई, जबकि सचिव और कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के दस्तावेजों में भी नियमों के अनुरूप कमियां सामने आईं।

मसूरी छात्रसंघ चुनाव में 1800 को झटका (टचम-मूट टीतंज) चुनाव अधिकारियों के अनुसार, उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी की उम्र 22 वर्ष चार माह पाई गई, जबकि लिंगदोह सिफारिशों के तहत निर्धारित अधिकतम उम्र 22 वर्ष है। वहीं, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के दो अन्य प्रत्याशियों के परिणाम घोषित नहीं होने और क्रेडिट बैरड सिस्टम की निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होने के कारण उनके नामांकन भी प्रारंभिक जांच में निरस्त कर दिए गए। इन तीन नामांकन के खारिज होने के बाद फिलहाल उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर एक-एक प्रत्याशी के ही मैदान में रहने की स्थिति बन गई है। हालांकि अंतिम निर्णय नामांकन पत्रों की पूरी जांच और अंतिम सूची जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला: एमपीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए तीन प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इनमें मसूरी छात्र संगठन से मनन, एनएसयूआई से



विकास सिंह और एबीवीपी से वेदांत थपलियाल शामिल हैं। सचिव पद पर अंकित रौतेला, रिया, प्रियांशु और आशुतोष जोशी ने नामांकन दाखिल किया है। उपाध्यक्ष पद पर गौरव सिंह गुसाई, सला. नी ने नामांकन किया है। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए करिश्मा डुमोगा और संन्या ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान हल्की नोकझोंक: नामांकन प्रक्रिया के दौरान कॉलेज परिसर में दो छात्र गुटों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया। चुनाव अधिकारी अमिताभ भट्ट और प्राचार्य डॉ. सुनील पंवार ने बताया कि, चुनाव प्रक्रिया में लिंगदोह सिफारिशों का हर हाल में पालन कराया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में तीन नामांकन पत्रों में खामियां मिलने पर उन्हें तत्काल निरस्त किया गया

है। 25 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच के बाद अंतिम प्रत्याशी सूची जारी की जाएगी, इसके बाद चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। 29 सितंबर को मतदान, आईडी के बिना प्रवेश नहीं: चुनाव अधिकारी ने बताया कि, 29 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना शुरू होगी। कॉलेज परिसर में बिना वैध आईडी कार्ड किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और केवल आईडी कार्ड के आधार पर ही मतदान की अनुमति होगी। चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। कॉलेज परिसर में बाहरी या प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। मसूरी पुलिस की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरी चुनाव प्रक्रिया एसडीएम मसूरी और कॉलेज प्रशासक के निर्देशन में कराई जा रही है।

कूनों में नामीबियाई चीता गौरव की मौत, 10 साल से अधिक थी उम्र, भारत में अब 55 चीते

श्यापुर: कूनों नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट चीता के लिए एक दुःखद खबर सामने आई है। नामीबिया से भारत लाए गए चीता गौरव की सोमवार 21 सितंबर 2026 को उपचार के दौरान मौत हो गई। गौरव की उम्र 10 वर्ष से अधिक बताई गई है। चीता गौरव का 12 सितंबर को जंगल से रेस्क्यू किया गया। सोमवार की शाम कूनों नेशनल पार्क की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, 12 सितंबर 2026 को गौरव को जंगल से रेस्क्यू किया गया था। निगरानी के दौरान वह कमजोर और सुस्त नजर आया था। चिकित्सकीय जांच में वह बेहद कमजोर पाया गया और उसके शरीर में मांसपेशियों की क्षति तथा गंभीर डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखाई दिए। छंउपइपंद बीममजी क्मतंतअ कपमे पद इनदव

कूनों नेशनल पार्क की ओर से जारी प्रेस नोट (मूट टीतंज) गौरव की मौत का सटक कारण पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। इसके बाद गौरव को तत्काल उपचार दिया गया और बेहतर निगरानी एवं आगे के प्रबंधन के लिए पालपुर स्थित क्वारंटीन बोमा (फठ) में रखा



जताई गई थी। लगातार उपचार और देखभाल के बावजूद गौरव की हालत में सुधार नहीं हो सका और 21 सितंबर को शाम करीब 4 बजे उसने दम

तोड़ दिया। अधिकारियों के मुताबिक, गौरव की मौत का सटीक कारण पोस्टमार्टम और लिए गए सैंपलों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

कूनों नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर आर. थिरुकरुल ने बताया कि "12 सितंबर 2026 को गौरव को जंगल से रेस्क्यू किया गया था। निगरानी के दौरान वह कमजोर और सुस्त नजर आया था। चिकित्सकीय जांच में वह बेहद कमजोर पाया गया और उसके शरीर में मांसपेशियों की क्षति तथा गंभीर डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखाई दिए। गौरव को तत्काल उपचार दिया गया और बेहतर निगरानी एवं आगे के प्रबंधन के लिए पालपुर स्थित क्वारंटीन बोमा (फठ) में रखा गया। प्रारंभिक चिकित्सकीय जांच में उसके शरीर में किसी अंतर्निहित पुरानी बीमारी की आशंका जताई गई। मौत का अंतिम कारण पोस्टमार्टम और सैंपल जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।"

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे की राह और होगी आसानय जाजमऊ पुल से जुड़ेगा, छम्पा ने किया कंपनी का चयन



कानपुर : प्रदेश सरकार की ओर से 13 जुलाई को कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस वे का तोहफा दिया गया था, जिसके बाद अब जाजमऊ पुल पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पुल से एक एलीवेटेड सड़क बनाते हुए उसे सीधे कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस वे से जोड़ने की तैयारी है। कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस वे शुरू होने के करीब 70 दिनों बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अफसरों ने अब एक कंपनी का चयन कर दिया है, जो उस पूरे रूट का सर्वे करेगी। करीब दो माह तक फिजिबिलिटी टेस्ट समेत अन्य परीक्षण करने के बाद कंपनी की ओर से पूरी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एनएचएआई अफसरों को सौंपी जाएगी।

रोजाना पुल से गुजरते हैं 50 से 80 हजार वाहन सवार : एनएचएआई अफसरों की रिपोर्ट के मुताबिक, रोजाना कानपुर में जाजमऊ गंगा पुल से 50 से 80 हजार वाहनों की आवाजाही होती है, जैसे ही कोई वाहन सवार जाजमऊ स्थित गंगा पुल पर पहुंचता है तो यहां पर वाहनों की अधिकता के चलते वाहन की गति धीमी करनी पड़ जाती है। इसके बाद सीधे आगे चलने पर तीन से चार किलोमीटर बाद कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस वे का कट आता है, लेकिन, यहां बहुत अधिक जाम जैसी स्थिति रहती है। यही स्थिति और नजारा पुल के दूसरी ओर भी दिखता है, जब वाहन सवार कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस वे से नीचे उतरकर जाजमऊ गंगा पुल की ओर पहुंचते हैं और फिर शहर के अंदर अपने गंतव्य तक जाते हैं। एनएचएआई निदेशक पंकज यादव ने बताया कि एक कंपनी का चयन किया गया है, कंपनी के प्रतिनिधियों को बताया गया कि वह पूरे रूट की ट्रैफिक स्टडी करेंगे, तकनीकी तौर पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करें, फिर जो निष्कर्ष सामने आएगा उसके आधार पर फैसला किया जाएगा कि किस तरह एलीवेटेड रोड को बनाना है, उसकी लंबाई, चौड़ाई का अध्ययन कराएंगे, पुल से एक्सप्रेस वे तक जाम न लगे, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा, उन्होंने कहा कि इस काम के लिए मंत्रालय से निर्देश मिल गए हैं, जल्द से जल्द डीपीआर तैयार करवाएंगे।

एनएचएआई अफसरों का कहना था कि मौजूदा समय में कानपुर से लखनऊ जाने के लिए केवल जाजमऊ गंगा पुल का ही विकल्प है, गंगा बैराज के रास्ते सड़क क्रासिंग होते हुए लखनऊ जाने में वाहन सवारों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि पुल पर बहुत अधिक लोड होने के चलते भी चौपटिया वाहन सवार पट्टों जाम में फंसते हैं, ऐसे में अगर जाजमऊ गंगा पुल से कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे को सीधे एलीवेटेड सड़क से जोड़ दिया जाएगा तो लाखों राहगीर राहत की सांस लेंगे। भाजपा सांसद रमेश अवरुथी ने बताया कि 13 जुलाई को कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस वे शुरू होने के बाद जाजमऊ गंगा पुल से कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने 12 अगस्त को ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को पत्र भेज दिया था, जानकारी मिली है कि एनएचएआई ने इसके लिए कंपनी तय कर दी है जो अपनी ओर से डीपीआर तैयार करेगी।

हापुड़ में एंटी करप्शन टीम का एक्शन: 50 हजार की रिश्वत लेते कानूनगो विजेंद्र कुमार गिरफ्तार

हापुड़: हापुड़ जिले की धौलाना तहसील में बुधवार को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वतखोरी के आरोप में कानूनगो विजेंद्र कुमार को 50 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि जमीन के विवाद में कार्रवाई रोकने के बदले डेढ़ लाख रुपये मांगे गए थे, बुधवार को रिश्वत की पहली किस्त देने के लिए शिकायतकर्ता को तहसील के सामने स्थित क्लीनिक पर बुलाया गया था, जैसे ही 50 हजार रुपये दिए गए, पहले से निगरानी कर रही मेरठ की एंटी करप्शन टीम ने कानूनगो को घर दबोचा। जमीन पैमाइश के नाम पर मांगी थी डेढ़ लाख की घूस: कार्रवाई के बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया और कई लेखपाल व कर्मचारी थाने पहुंच गए, इस दौरान पुलिस और कर्मचारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, ग्राम धौलाना निवासी डॉक्टर कृष्णपाल सिंह के मुताबिक ग्राम समाना में उनकी करीब डेढ़ बीघा कृषि भूमि है, भूमि की पैमाइश को लेकर आसपास के किसानों ने जिलाधिकारी कोर्ट में धारा 24 के तहत केस दर्ज कराया था। एंटी करप्शन टीम ने विज्ञाया जाल, 50 हजार लेते पकड़ा: रविवार को तहसील की टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश की थी और उनकी जमीन पर दूसरे का कब्जा होने की बात कही गई, आरोप है कि कानूनगो ने जमीन से छेड़छाड़ न करने के बदले डेढ़ लाख रुपये की मांग की थी, पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग की हेल्पलाइन पर दर्ज कराई, शिकायत की जांच के बाद टीम ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने का पूरा प्लान बनाया। 22 सदस्यों की टीम ने लिया एक्शन, थाने पर हुआ हंगामा: बुधवार को क्लीनिक पर पहली किस्त देने के लिए बुलाया गया था, जहाँ 22 सदस्यों की टैप टीम ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया, कार्रवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसे अहम साक्ष्य जुटाए गए हैं, गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पटवारी और अन्य कर्मचारी थाने पहुंचकर कानूनगो को छुड़ाने की मांग करने लगे, हालांकि एंटी करप्शन टीम सभी दबावा, को दरकिनार कर आरोपी को अपने साथ ले गई। आरोपी कानूनगो का पुराना अपराधिक रिकॉर्ड आया सामने: जांच में सामने आया है कि आरोपी कानूनगो विजेंद्र कुमार के खिलाफ पहले से भी मुकदमा दर्ज है, मुरादाबाद में तैनाती के दौरान भी उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ था जो अभी पेंडिंग है, उस मामले में कोर्ट से रै-जमानती



आने वाले दो दिनों में भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, षड्क कंट्रोल रूम 9701999645 टोलफ्री: 1800 425 1980 व्हाट्सएप: 9701999676 नंबरों पर संपर्क



गोवर्धन उपाध्याय वरंगल शहर से



भारी बारिश पर सतर्क रहना चाहिए। इमरजेंसी सेवाओं के लिए षड्क कंट्रोल रूम 9701999645 टोलफ्री: 1800 425 1980 व्हाट्सएप: 9701999676 नंबरों पर संपर्क करें। रेस्क्यू टीम, मशीनें तैयार रखें: बल्लिया कमिश्नर टी. वेंकन्ना अधिकारियों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर वेंकन्ना के निर्देश षड्क 24 सितंबर आने वाले दो दिनों में भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, इस पृष्ठभूमि में ग्रेटर वरंगल शहर के लोग, अधिकारी सतर्क रहें, षड्क कमिश्नर टी. वेंकन्ना ने कहा। भारी बारिश की पृष्ठभूमि में शहर में कोई अग्रिय स्थिति न आए, पहले से कदम उठाएं, अधिकारियों को निर्देश दिया। गुरुवार को षड्क इंजीनियरिंग, सेनिटेशन, टाउन प्लानिंग, क्लृ आदि विभागों के अधिकारियों के साथ कमिश्नर टी. वेंकन्ना ने टेली कॉन्फ्रेंस आयोजित की। शहर में बारिश की स्थिति, जलमराव वाले इलाके, इमरजेंसी में उठाने वाले राहत कदम, स्टाफ, मशीनों की उपलब्धता आदि विषयों पर समीक्षा की। इस अवसर पर हर विभाग सतर्क रहे, जमीनी स्तर पर स्थिति पर समय-समय



पर नजर रखते हुए जरूरी जगह तुरंत प्रतिक्रिया दें, कमिश्नर ने सुझाव दिया। विभागों के बीच समन्वय और मजबूत कर लोगों को कोई परेशानी न हो, कदम उठाएं, निर्देश दिया। इमरजेंसी स्थिति में तुरंत राहत कदम उठाने के लिए जेसीबी, डीवाटरिंग मोटर, ट्रैक्टर, अन्य जरूरी मशीनें, उपकरण तैयार रखें, कमिश्नर ने निर्देश दिया। जरूरी इलाकों में स्टाफ, मशीनों को बिना देर किए पहुंचाने के लिए पहले से योजना तैयार करें, सुझाव दिया। षड्क गिरना, सड़कों पर बाढ़ का पानी जमा होना, बिजली से जुड़ी समस्याएं, नालियों का उफानना या अन्य इमरजेंसी स्थिति आते ही संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंच कर तुरंत राहत कदम उठाएं, स्पष्ट किया। भारी बारिश के कारण खतरनाक स्थिति बनने की संभावना वाले निचले इलाकों को पहले ही पहचानें, कमिश्नर ने निर्देश दिया। स्थिति बिगड़ने पर उन इलाकों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के लिए पहले से इंतजाम करें, जरूरत के हिसाब से सुरक्षित जगह, राहतधन्युर्वस केंद्र स्थापित कर लोगों को जरूरी सुविधाएं देने के लिए कदम उठाएं, अधिकारियों को

समन्वय से काम करते हुए शहर की स्थिति की लगातार निगरानी करें, कमिश्नर ने सुझाव दिया। जमीनी स्तर पर कोई समस्या दिखने पर तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देकर, बिना देर किए समाधान के कदम उठाएं, निर्देश दिया। लोगों से बारिश, जलमराव, बाढ़ का पानी, पेड़ गिरना आदि समस्याओं पर शिकायतें, जानकारी लेने के लिए षड्क मुख्यालय में 24 घंटे कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, कमिश्नर ने कहा। इमरजेंसी स्थिति में लोग टोलफ्री: 1800 425 1980 कंट्रोल रूम: 9701999645 व्हाट्सएप: 9701999676 नंबर, पर संपर्क करें। लोग इमरजेंसी स्थिति में तुरंत कंट्रोल रूम को जानकारी दें, अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए सतर्क रहें, कमिश्नर टी. वेंकन्ना ने अपील की। लोगों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हुए षड्क प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, किसी भी इमरजेंसी स्थिति का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए बल्लिया अधिकारी रेस्क्यू, क्लृ टीम, स्टाफ, मशीनें तैयार हैं, कमिश्नर वेंकन्ना ने कहा।

एमपीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव के नामांकन के पहले ही दिन चुनावी माहौल गरमा गया. एबीवीपी के तीन प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हुए.

मसूरी: एमपीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव के नामांकन के पहले ही दिन चुनावी माहौल गरमा गया, नामांकन पत्रों की प्रारंभिक जांच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के तीन प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों में खामियां मिलीं, जिसके बाद नामांकन पत्र को निरस्त करने की मांग को लेकर एनएसयूआई समेत अन्य छात्र नेताओं ने कॉलेज परिसर और गेट पर जमकर हंगामा किया।

मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में नामांकन के पहले ही दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) को बड़ा झटका लगा है, नामांकन पत्रों की प्रारंभिक जांच में एबीवीपी की ओर से उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर दाखिल किए गए तीन नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए, इनमें उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी की उम्र निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई, जबकि सचिव और कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के दस्तावेजों में भी नियमों के अनुरूप कमियां सामने आईं। मसूरी छात्रसंघ चुनाव में 10 टर्न को झटका (टक्क-नोट टॉर्न) चुनाव अधिकारियों के अनुसार, उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी की उम्र 22 वर्ष चार माह पाई गई, जबकि लिंगदोह सिफारिशों के तहत निर्धारित अधिकतम उम्र 22 वर्ष है, वहीं, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के दो अन्य प्रत्याशियों के परिणाम घोषित नहीं होने और क्रेडिट बेस्ड सिस्टम की निर्धारित शर्त पूरी नहीं होने के कारण उनके नामांकन भी प्रारंभिक जांच में निरस्त कर दिए गए। इन तीन नामांकन के खारिज होने के बाद फिलहाल उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर एक-एक प्रत्याशी के ही मैदान में रहने की स्थिति बन गई है। हालांकि अंतिम निर्णय नामांकन पत्रों की पूरी



जांच और अंतिम सूची जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। उपाध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला: एमपीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए तीन प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, इनमें मसूरी छात्र संगठन से मनन, एनएसयूआई से विकास सिंह और एबीवीपी से वेदांत थपलियाल शामिल हैं, सचिव पद पर अंकित रीतेला, रिया, प्रियांशु और आशुतोष जोशी ने नामांकन दाखिल किया है, उपाध्यक्ष पद पर गौरव सिंह गुसाई, सहसचिव पद पर ईशा और कोषाध्यक्ष पद पर सलोनी ने नामांकन किया है, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए करिश्मा डुमोगा और संघ्या ने नामांकन दाखिल किया, नामांकन के दौरान हल्की नोकझोंक: नामांकन प्रक्रिया के दौरान कॉलेज परिसर में दो छात्र गुटों

के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया, चुनाव अधिकारी अमिताभ मट्ट और प्राचार्य डॉ. सुनील पवार ने बताया कि, चुनाव प्रक्रिया में लिंगदोह सिफारिशों का हर हाल में पालन कराया जा रहा है, प्रारंभिक जांच में तीन नामांकन पत्रों में खामियां मिलने पर उन्हें तत्काल निरस्त किया गया है, 25 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच के बाद अंतिम प्रत्याशी सूची जारी की जाएगी, इसके बाद चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी।

29 सितंबर को मतदान, आईडी के बिना प्रवेश नहीं: चुनाव अधिकारी ने बताया कि, 29 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मतदान कराया जाएगा, मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना शुरू होगी, कॉलेज परिसर में बिना वैध आईडी कार्ड किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और केवल आईडी कार्ड के आधार पर ही मतदान की अनुमति होगी, चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है, कॉलेज परिसर में बाहरी या प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी, मसूरी पुलिस की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पूरी चुनाव प्रक्रिया एसडीएम मसूरी और कॉलेज प्रशासक के निर्देशन में कराई जा रही है।

हनमकोंडा कलेक्ट्रेट से विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी, म्युनिसिपल कमिश्नर, तहसीलदार, एमपीडीओ के साथ गूगल मीट के जरिए जिला कलेक्टर की बैठक



समस्याएं आने वाले इलाकों की जानकारी लेकर, उन इलाकों में पहले से कदम उठाने पर अधिकारियों को कलेक्टर ने कई निर्देश जारी किए। इस अवसर पर कलेक्टर चाहत बाजपेयी ने कहा जिले के वेलेर, आत्मकूर मंडलों में बुधवार को हुई बारिश से ज्यादा बारिश दर्ज हुई। आज, कल (गुरुवार, शुक्रवार) भी अचानक भारी बारिश दर्ज होने पर नाले, नालियां उफन कर सड़कों पर बाढ़ का पानी आने की संभावना होने से पहले से सावधानी के कदम अधिकारी उठाए। तालाबों, नालों, नालियों की स्थिति की समय-समय पर निगरानी करें, बाढ़ का पानी सड़कों पर आने की संभावना वाले इलाकों को पहले ही पहचान कर लोगों को परेशानी न हो, कदम उठाएं, अधिकारियों को निर्देश दिया। जलरूरी इलाकों में रेत की बोरियां तैयार रखने का सुझाव दिया। जिले के सभी तालाबों में फिलहाल कितना पानी है, सिंचाई विभाग के अधिकारी समय-समय पर जानकारी इकट्ठा करें, कलेक्टर ने निर्देश दिया।

बारिश बढ़ने पर तालाबों के जलस्तर, पानी के बहाव की स्थिति की लगातार निगरानी करें, उस विभाग के अधिकारियों को सुझाव दिया। भारी बारिश के समय अधिकारी अपने दायरे में स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध रहें, कोई समस्या आते ही जमीनी स्तर पर तुरंत प्रतिक्रिया दें, कलेक्टर ने स्पष्ट किया। पहले बारिश के समय मुश्किल आने वाले इलाकों को पहचान कर, वहां फिलहाल उठाने वाले एहतियाती कदमों को देखें, निर्देश दिया। ग्रेटर वारंगल नगर निगम की सीमा के कई इलाकों में नालियों में जमा प्लास्टिक कचरा, अन्य कचरा तुरंत हटाएं। मुख्य नालियों में बाढ़ का पानी न रुके, जलरूरी कदम उठाएं, सुझाव दिया। ग्रेटर वारंगल



नगर निगम की सीमा में और सभी मंडलों में जरूरी इलाकों में तत्काल मदद के लिए जेसीबी, अन्य मशीनें तैयार रखने का कलेक्टर ने निर्देश दिया। कहीं भी समस्या आने पर तुरंत संबंधित अधिकारी सतर्क रह कर मदद के कदम उठाएं, सुझाव दिया। भारी बारिश की पृष्ठभूमि में कंट्रोल रूम में अधिकारी, कर्मचारी 24 घंटे उपलब्ध रहें, कदम उठाएं, अधिकारियों को कलेक्टर ने निर्देश दिया। लोगों से आने वाली शिकायतों, जरूरी सूचना पर तुरंत प्रतिक्रिया दें, सुझाव दिया। लगातार बारिश होने के समय अधिकारी और सतर्क रहें, कहा। कहां समस्या आने की संभावना है पहले ही पहचान कर, वहां जरूरी कदम उठाएं, निर्देश दिया। सड़कों, नालों, नालियों, तालाबों, ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति पर लगातार नजर रखें, सुझाव दिया। जिले में कहीं भी बारिश के कारण हुए नुकसान पर तुरंत जानकारी की रिपोर्ट दें। लोगों को समय-समय पर सतर्क करते हुए अधिकारी कदम उठाएं। लगातार बारिश होने पर अधिकारी और सतर्क रहें। लोगों को कोई परेशानी न हो, अधिकारी समन्वय के साथ काम करें, कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया। इस गूगल मीट में जिला अतिरिक्त कलेक्टर एन. रवि, ग्रेटर वारंगल नगर निगम कमिश्नर वेकन्ना, हनमकोंडा, परकाल आरडीओ वेंकटेश, डीएस वेकन्ना, जेडपी सीईओ शेषाद्री, परकाल म्युनिसिपल कमिश्नर पवन, सिंचाई विभाग डई मंगीलाल, सड़क, भवन विभाग डई देविका चौहान, अन्य विभागों के जिला अधिकारी, सभी मंडलों के तहसीलदार, एमपीडीओ, अन्य अधिकारी शामिल हुए।

एसआई कूचिपूडी जगदीश के साथ ड्राइवर कोत्तापल्ली राकेश को भी गंभीर चोटें लगने की जानकारी है। काकरवाई गांव के रहने वाले राकेश के सिर में गंभीर चोट लगने की जानकारी है।



गोवर्धन उपाध्याय की रिपोर्ट तिरुमलायपालेम एसआई कूचिपूडी जगदीश का रोड एक्सीडेंट लॉरी की टक्कर से पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त एसआई के साथ ड्राइवर को गंभीर चोटें खम्मम जिला



तिरुमलायपालेम पुलिस स्टेशन एसआई कूचिपूडी जगदीश सड़क हादसे का शिकार हुए। विनायक विसर्जन समारोह के दौरान मंडल के कई गांवों में ड्यूटी करने के बाद पिंडिप्रोलु गांव से तिरुमलायपालेम पुलिस स्टेशन वापस आते समय यह हादसा होने की जानकारी है। गुरुवार तड़के लगभग 1 बजे भवानी होटल के पास एसआई जगदीश और उनके ड्राइवर पुलिस वाहन में सफर कर रहे थे तभी लॉरी ने टक्कर मार दी, जानकारी है। इस हादसे में पुलिस वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने की जानकारी है। इस हादसे में एसआई कूचिपूडी जगदीश के साथ ड्राइवर कोत्तापल्ली राकेश को भी गंभीर चोटें लगने की जानकारी है। काकरवाई गांव के रहने वाले राकेश के सिर में गंभीर चोट लगने की जानकारी है। हादसा होते ही घायलों को इलाज के लिए तिरुमलायपालेम अस्पताल ले जाया गया, बाद में बेहतर इलाज के लिए खम्मम के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। हालांकि एसआई जगदीश, ड्राइवर राकेश की सेहत की स्थिति पर पूरी जानकारी आनी बाकी है। हादसे के कारण, लॉरी की डिटेल्स, चोटों की गंभीरता पर आधिकारिक जानकारी आनी बाकी है।

मेदक में जल्द शुरू होगा सेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी किचन

मेदक, 24 सितंबर (बपअपब छंजपवद)

स्कूल ब्रेकफास्ट प्रोग्राम के तहत मेदक मार्केट यार्ड में स्थापित सेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी किचन जल्द शुरू किया जाएगा। इस किचन के माध्यम से मेदक और नरसापुर विधानसभा क्षेत्रों के 11 मंडलों में स्थित 395 सरकारी स्कूलों और 10 सरकारी जूनियर कॉलेजों के 29,183 विद्यार्थियों को प्रतिदिन पोषिक नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। छप्प के सहयोग से तैयार मेनू के अनुसार रोज अलग-अलग नाश्ता और एक दिन छोड़कर दूध दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, उपस्थिति और पढ़ाई पर एकाग्रता को बढ़ाना है।



पुष्कर कार्य समय पर पूरे करें: कलेक्टर

निर्मल, 24 सितंबर (बपअपब छंजपवद)

गोदावरी पुष्कर के लिए बासर आने वाले श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश जिला कलेक्टर भावेश मिश्रा ने अधिकारियों को दिए। गुरुवार को कलेक्टर ने बासर में पुष्कर कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की पार्किंग, वीआईपी और वीवीआईपी पार्किंग, हेलिपैड निर्माण स्थलों का जायजा लिया। कलेक्टर ने श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए मार्गवार पार्किंग व्यवस्था करने, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सभी कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। बाद में उन्होंने नए तहसीलदार कार्यालय भवन के लिए प्रस्तावित स्थल का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर मैसा सब कलेक्टर अजमीरा संकेत कुमार, आर एंड बी ईई सुभाष, तहसीलदार पवन चंद्र सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।



कृषि, प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों के निर्यात पर किसानों को जागरूक करना चाहिए जिला कलेक्टर संदीप कुमार झा एफपीओ के जरिए कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए, जिला कलेक्टर संदीप कुमार झा



गोवर्धन उपाध्याय की रिपोर्ट

जनगांव एफपीओ के जरिए कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए कृषि, प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों के निर्यात पर किसानों को जागरूक करना चाहिए जिला कलेक्टर संदीप कुमार झा एफपीओ के जरिए कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए, जिला कलेक्टर संदीप कुमार झा ने कहा। गुरुवार को, जिला एकीकृत कलेक्टर कार्यालय के मेन कॉन्फ्रेंस हॉल में कृषि उत्पादों के निर्यात पर किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (थ्य), जैविक किसानों, कृषि उद्यमियों, व्यापारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर संदीप कुमार झा की अध्यक्षता में कृषि, प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों के निर्यात विकास संस्था (भारत सरकार संस्था - थ्य) की ओर से जिला स्तरीय निर्यात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा, कृषि, प्रोसेस्ड फूड उत्पादों के निर्यात विकास संस्था (थ्य) भारत सरकार की संस्था है। कृषि उत्पादों को विदेशों में निर्यात करने के लिए जरूरी लाइसेंस, गुणवत्ता मानक, आयातक-निर्यातकों के बीच जुड़ाव, सप्लाय चेन की स्थापना जैसे विषयों में थ्य प्रमुख नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है, बताया जिले में निर्यात के अच्छे मौके हैं, खासतौर पर विट्टी मुत्तालु चावल के निर्यात की ज्यादा मांग है। डब्ज-1010 पारावॉयल्ड राइस किस्म का विदेशों में अच्छा बाजार है, तेलंगाना से इस किस्म के चावल का 22 हजार मीट्रिक टन फिलीपींस को निर्यात किया गया है, बताया जिले में लगभग 44 हजार एकड़ में डब्ज-1010 किस्म की खेती हो रही है, जो जिले की धान की खेती का 26 प्रतिशत हिस्सा है, कहा। इस किस्म के चावल को विदेशी बाजार में लगभग 3,600 रुपये तक दाम मिल रहा है, बताया। भारत कृषि निर्यात योजना स्क्रीम के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने के मौकों का किसान, एफपीओ उपयोग करें, अपील

की जिले में मौजूद 22



एफपीओ, किसान, निर्यात के मौकों का सही उपयोग करें, थ्य। से मिलने वाले सहयोग का उपयोग कर अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों के लिए बाजार बढ़ाएं, सुझाव दिया। जिले के किसानों, एफपीओ को सीधे बाजार के मौके दिलाने के लिए आने वाले 30 दिनों में खरीदार-विक्रेता बैठकें आयोजित करने का सुझाव दिया। साथ ही एफपीओ मेले भी आयोजित करें, किसानों को निर्यात बाजारों से जोड़ना चाहिए, कहा। विट्टीमुत्तालु सुगंधित चावल को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग विकास योजना (पूडभंड) में एक जिला - एक उत्पाद (व्यव) सूची में मौजूद विशेष उत्पाद के रूप में विकसित करना चाहिए। शुद्ध बीज, विशेष मिलिंग, विशेष लॉट, डीएनए टेस्ट के जरिए मिलावट रोकना, पहले से खरीदारों के समझौतों के साथ प्रीमियम ब्रांड के रूप में तैयार करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए, कहा। फिलहाल खरीफ फसल कटाई के चरण में होने से यासंगी 2026-27 से अवशेष निर्यातित बलस्टर शुरू करना चाहिए,

कहा। जिले के किसान उत्पादक संघ (थ्य), राइस मिलर, प्रोसेसर क्लब्स पोर्टल के जरिए थ्य। म-रूडव पंजीकरण ले, सुझाव दिया। थ्य 22000 थ्य प्रमाणीकरण थ्य। पंजीकरण के लिए जुने जाने वाले राइस मिलों की सूची तैयार करनी चाहिए, कहा। यासंगी 2026-27 के लिए अवशेष नियंत्रित चावल बलस्टर स्थापित कर, मांग लेने वाले थ्य, निर्यातक की पहचान करनी चाहिए, कहा। इससे पहले कृषि उत्पादों के निर्यात से जुड़े मौके, गुणवत्ता मानक, मार्केटिंग, थ्य। की मदद, निर्यात प्रक्रिया पर इस जागरूकता कार्यक्रम में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए एपीआईडीए एसिस्टेड मैनेजर सुकेश ने विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम में जिला कृषि अधिकारी के, अंबिका सोनी, मत्स्य विभाग अधिकारी राणा प्रताप, जिला उद्यान विभाग अधिकारी नरसय्या, एपीडी नरुद्दीन, थ्य। एसिस्टेड मैनेजर सुकेश, नाबार्ड डीडीएम विजय, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रतिभा, कृषि सखी, जिले के एफपीओ, एफपीसी के प्रतिनिधि आदि शामिल हुए।

एशियन गेम्स 2026: कौन हैं रोशिबिना देवी? जिन्होंने लगातार तीसरे एशियन गेम्स में जीता मेडल



प: भारतीय वुशु स्टार रोशिबिना देवी ने एशियन गेम्स में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। उन्हें गुरुवार को एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं के 60kg सांडा इवेंट में सिल्वर मेडल जीता, फाइनल मुकाबले में रोशिबिना को चीन की झांग शियाओयू से 2-0 से हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें सिल्वर मेडल पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि ये एशियन गेम्स में उनका लगातार तीसरा मेडल है। इससे पहले रोशिबिना ने 2018 में जकार्ता और 2023 में हांगकॉक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उन्होंने एशियन गेम्स में भारत के लिए 13वां मेडल जीता और मीजूटा इवेंट में भारत के पास अब तक 14 मेडल हो गए हैं। अपने रजत पदक के महत्व के बारे में रो.

शिबिना ने कहा, 'यह एशियाई खेलों में मेरा तीसरा पदक है। सभी वुशु खिलाड़ी पदक जीतने की उम्मीद करते हैं, वे भी मेरी तरह पदक जीतना चाहते हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को प्रेरित करना चाहती हूँ, मैं भी उनसे प्रेरणा लेना चाहती हूँ। आगामी खेलों 25 वर्षीय रोशिबिना फाइनल के बाद कहा, 'जो कुछ हुआ, वह मेरी वजह से नहीं हुआ। यह महासंघ का फैसला था कि मुझे एशियाई खेलों के लिए चुना जाए। भारतीय वुशु संघ ने जो भी फैसला लिया, मुझे लगता है कि वह सही था।' उन्होंने दिव्यांशी के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कहा, 'मैं इसे नजरअंदाज करूंगी, मैं सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहती हूँ।'

क्या था विवाद? रोशिबिना को आखिरी

समय में भारतीय वुशु टीम में शामिल किया गया था, जिससे यह मामला विवादों से घिर गया। दरअसल खेल मंत्रालय द्वारा 22 अगस्त को जारी किए गए स्ववाद में महिलाओं के 60kg सांडा कैटेगरी में दिव्यांशी चौधरी का नाम था, लेकिन वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया (I) ने दिव्यांशी के घोटिल होने की जानकारी दी, जिससे रोशिबिना के टीम में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया। इसके बाद दिव्यांशी ने एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया कि उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था ताकि वुशु स्ववाद में रोशिबिना को शामिल किया जा सके, इसी वजह से फेडरेशन ने मुझे घोटिल घोषित कर दिया। हालांकि मैंने सिलेक्शन ट्रायल में रोशिबिना को हराया था, लेकिन कुछ दिनों बाद दिव्यांशी ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें कहा कि वे फेडरेशन के फैसले को समझती हैं और अपनी संहता को प्राथमिकता देंगी। भारतीय वुशु स्टार रोशिबिना देवी ने जीता सिल्वर मेडल। भारतीय वुशु स्टार रोशिबिना देवी ने जीता सिल्वर मेडल (1-18)। कौन हैं रोशिबिना देवी? 2000 को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में हुआ था। यह भारतीय एथलीट वुशु के सांडा कैटेगरी में हिस्सा लेती हैं, जो वुशु का एक कॉम्बेट डिस्चिप्लिन खेल है, जिसमें स्ट्राइकिंग और कुछ थ्रोइंग

एशियन गेम्स के दूसरे दिन भारत ने जीते 4 मेडल, निशानेबाजी में जीता पांचवां मेडल, देखें पदक तालिका में भारत कहां खड़ा है?

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अब तक भारत अपने 6 मेडल में से 5 मेडल निशानेबाजी में हासिल कर चुका है। रविवार को भारत को दो रजत पदक निशानेबाजी में मिले थे और आज दूसरे दिन भी निशानेबाजी में तीन पदक जीत चुका है। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम को पदकजापान के नागोया में खेले जा रहे 20वें एशियन गेम्स के दूसरे दिन सोमवार को रुद्राक्ष पाटिल, हिमांशु डिल्लों और पार्थ माने ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत को तीसरा पदक दिलाया, पूर्व विश्व चैंपियन 22 वर्षीय रुद्राक्ष, 20 वर्षीय हिमांशु और 18 वर्ष के माने ने 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत को 1890.1 अंक दिलाए, जिससे वो चीन से पीछे दूसरे नंबर पर रहे, चीन की टीम 1899.0 अंक के साथ पहले स्थान पर रही, जबकि दक्षिण कोरिया की टीम को 1884.2 अंक के साथ कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। रुद्राक्ष पाटिल, हिमांशु डिल्लों और पार्थ माने रुद्राक्ष पाटिल, हिमांशु डिल्लों और पार्थ माने (1-18) पुरुष के 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में भी मेडल टीम को रजत पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने के बाद रुद्राक्ष



पाटिल ने पुरुष 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत को चौथा मेडल दिला दिया। जबकि हिमांशु डिल्लों ने इसी मुकाबले में रजत पदक जीतकर भारत को पांचवां मेडल दिलाया। डिल्लों ने 252.4 अंक जुटाकर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि रुद्राक्ष 230.9 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे, चीन के निहाओ शेंग ने 254.2 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। रुद्राक्ष पाटिल और हिमांशु डिल्लों रुद्राक्ष पाटिल और हिमांशु डिल्लों (1-18) निशानेबाजी में भारत का पांचवां पदक निशानेबाजी में भारत ने दूसरे दिन तीन पदक जीते जिससे इस खेल में देश के पदकों की संख्या पांच हो गई है। रविवार को इलावेनिल, सोमम मस्कर और विदरसा विनोद ने

महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत के अभियान की शानदार शुरुआत की थी, इसके बाद इलावेनिल ने व्यक्तिगत स्पर्धा में भी एक और रजत पदक अपने नाम किया था। रुद्राक्ष पाटिल और हिमांशु डिल्लों रुद्राक्ष पाटिल और हिमांशु डिल्लों (1-18) डिल्लों ने भारत को मिला पहला पदक। भारत की सुधिका त्रिथाल ने सोमवार को महिला पारंपरिक 60 किग्रा मिश्रित मार्शल आर्ट (एमएमए) स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्हें सेमीफाइनल के अतिरिक्त दौर में सिंगापुर की हुई हून् टियो के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा, यह एशियाई खेलों में पदार्पण कर रही मिश्रित मार्शल आर्ट स्पर्धा में भारत का पहला पदक है, बता दें कि

एशियन गेम्स 2026: भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला हर मैच काफी ज्यादा रोमांचक होता है। लेकिन फैंस का उत्साह उस समय ज्यादा बढ़ जाता है जब ये मुकाबला क्रिकेट के मैदान में पहुंचता है। हालांकि जापान में जारी एशियाई खेलों के मैस क्रिकेट प्रतियोगिता में ऐसा फिक्सचर बनाया गया है, जिसकी वजह से ये दोनों टीमें सिर्फ मेडल मैच में ही आमने सामने हो सकती हैं। लेकिन सोमवार को महिला और पुरुष टेबल टेनिस टीमों के मुक, पहले में दोनों एडोसी देश आमने सामने आए, जिसमें एडोसी देश पाकिस्तान को बुरी तरह 3-0 से हार



का सामना करना पड़ा। इस शानदार जीत के साथ भारत की महिला टीम क्वार्टर फाइनल में जबकि मैस टीम प्रीक्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गई है। महिला टेबल टेनिस टीम का शानदार प्रदर्शन भारतीय महिला टीम

ने ग्रुप एफ में लगातार तीसरी जीत दर्ज कर शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने रविवार को अपने शुरुआती मुकाबलों में इंडोनेशिया और सिंगापुर को हराया था और इसके बाद चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को खिलाफ भी अपना दबदबा कायम रखा। पिछले एशियाई खेलों में महिला युगल में कांस्य पदक जीतने वाली सुतीथा मुखर्जी ने पाकिस्तान की अलीना खान को केवल 10 मिनट में 11-3, 11-3, 11-4 से हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद 17 वर्षीय सिद्धेला दास ने कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से

शेयर बाजार में दो दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स 332 अंक और निफ्टी 99 अंक संभलकर बंद



भारतीय शेयर बाजार में पिछले दो दिनों से जारी गिरावट के सिलसिले पर बुधवार को ब्रेक लग गया और घरेलू बेधमार्क सूचकांकों ने निचले स्तरों से रिकवरी दर्ज की। एफएमसीजी, रियल्टी और पीएसयू बैंकिंग शेयरों में आई मजबूत लिक्विडिटी ने बाजार को सहारा दिया। इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले से ठीक पहले कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी ने भी बाजार के सेंटिमेंट को मजबूती प्रदान की। कारोबार के अंत में, बीसे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 332.63 अंक (0.45%) की बढ़त के साथ 74,336.45 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 सूचकांक भी 99.00 अंक (0.43%) की तेजी लेकर 23,217.60 के स्तर पर सेटल हुआ।

तकनीकी मोर्चे पर, बाजार विश्लेषकों का कहना है कि निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 23,300 व 23,400 का दायरा रिकवरी को सीमित कर रहा है। व्यापक तकनीकी ढांचे में सुधार के लिए इंडेक्स का 23,500 के ऊपर टिकना जरूरी है। वहीं, नीचे की ओर 23,100 व 23,070 का क्षेत्र तत्काल सपोर्ट बना हुआ है। यदि निफ्टी 23,070 के नीचे फिसलता है, तो बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है जो इसे 23,000 व 22,800 के स्तर पर ला सकता है। निफ्टी के प्रमुख घटक शेयरों में एचडीएफसी लाइफ इश्योरेंस कंपनी, आईटीसी (पञ्ज) और एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कंपनी आज के टॉप गेनर्स के रूप में उभरे, जिन्होंने बेधमार्क सूचकांकों को मजबूती दी। इसके विपरीत, ब्रॉडर मार्केट में सुस्ती का माहौल रहा।

निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.01% और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.18% टूटकर बंद हुए। सेक्टरल प्रदर्शन में निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा पर गहरा दबाव देखा गया और इन दोनों क्षेत्रों में आज सबसे तीखी गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल निवेशकों का पूरा ध्यान अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजों और ब्याज दरों को लेकर केंद्रीय बैंक के आउटलुक पर टिका हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार, फेड वयरमें की संतुलित टिप्पणी बाजार की इस रिकवरी को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन यदि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में दोबारा उछाल आता है या ब्रैट ब्रूड ऑयल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल की तरफ बढ़ती हैं, तो घरेलू बाजार में एक बार फिर बिकवाली का दौर लौट सकता है।

अक्सर जल्दबाजी या एक छोटी सी लापरवाही के कारण लोग गलत नंबर पर पैसे ट्रांसफर कर बैठते हैं, ऐसे में क्या करें आइए जानते हैं.



नई दिल्ली: भारत में न्यू (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) आने के बाद से पैसे का लेन-देन बेहद आसान हो गया है। आज चाय की टपरी से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक, लोग अपने फोन का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। एक तरफ जहां यूपीआई ने देश को डिजिटल रफ्तार दी है, तो वहीं दूसरी ओर इसने एक अनजाने खतरे को भी जन्म दे दिया है। अक्सर जल्दबाजी या एक छोटी सी लापरवाही के कारण लोग गलत नंबर या गलत क्यूआर कोड पर पैसे ट्रांसफर कर बैठते हैं। ऐसे में मेहनत की गाड़ी कमाई किसी और के खाते में चली जाती है और लोग घबरा जाते हैं कि अब यह पैसा कभी वापस मिलेगा या नहीं। आज हम आपको बताते जा रहे हैं कि क्या गलत खाते में गया पैसा वापस आ सकता है और इसके लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे, क्या न्यू से भेजा हुआ पैसा तुरंत वापस हो सकता है?

इस सवाल का सीधा और साफ जवाब है 'नहीं', अगर आपने अपने मोबाइल ऐप में यूपीआई पिन दर्ज करके ट्रांज़ैक्शन पूरा कर दिया है, तो उस ट्रांज़ैक्शन को तुरंत कैसल या रिवर्स करने का कोई 'बटन' ऐप में नहीं होता, तकनीकी रूप से पैसा तुरंत सामने वाले के खाते में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका पैसा डूब गया। अगर आप सही समय पर सही प्रक्रिया अपनाते हैं, तो आपका पैसा वापस मिलने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। 1: सबसे पहले यूपीआई ऐप पर दर्ज करें 'विवाद' गलत ट्रांज़ैक्शन होते ही घबराने के बजाय सबसे पहले उसी यूपीआई ऐप (जैसे ढववहसम ब्ल, धैवदमम्, ब्लजज या ठम्ड) को ओपन करें जिससे आपने पैसे भेजे हैं। अपने ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री में जाएं, उस गलत लेन-देन को सिलेक्ट करें, वहां आपको 'लम्चवतज' 'लवइसमप' या 'त्येम' 'त्येचनजम' का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज करें। आप कि पैसा गलती से किसी और को ट्रांसफर हो गया है, 72 घंटे के भीतर अपने बैंक को दें सूचना सिर्फ ऐप पर शिकायत करना काफी नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक, गलत ट्रांज़ैक्शन के 72 घंटों के भीतर आपको अपने बैंक से संपर्क करना बेहद जरूरी है। आप बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपनी नजदीकी होम ब्रांच में जा सकते हैं। बैंक को ट्रांज़ैक्शन की तारीख, समय और सबसे महत्वपूर्ण 12 अंकों का न्यू नंबर प्रदान करें, यदि प्राप्तिकर्ता का खातानुरोध करता है, 3: छच्छ पोर्टल और आरबीआई लो, कपाल का सहारा लें। अगर ऐप और बैंक से बात करने के

बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो देश में यूपीआई का संचालन करने वाली संस्था छच्छ (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, वहां 'स्पेचनजम' लम्चतमेंस डमवीडपेउ' के तहत 'दबवततमबजसल' जतंदेमिमतमक जव 'दवजीमत' 'बबवनदज' विकल्प चुनकर अपनी शिकायत दर्ज करें, अगर 30 दिनों तक कोई हल नहीं निकलता, तो आप आरबीआई लो, कपाल (ल्ल ल्इवनकेउंद) के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, एक्सपर्ट टिप: हमेशा बरतें ये सावधानियां डिजिटल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इलाज से बेहतर बचाव है, किसी भी अनजान या नए नंबर पर बड़ा अमाउंट भेजने से पहले हमेशा 51 का टेस्ट ट्रांसफर करके सामने वाले का नाम जरूर कन्फर्म कर लें, जल्दबाजी में कभी भी पेमेंट्स न करें और सार्वजनिक 1 भी उसी बैंक में है, तो बैंक तुरंत कार्रवाई कर सकता है, दूसरे बैंक का मामला होने पर आपका बैंक उस संबंधित बैंक से संपर्क कर फंड को होल्ड करने का 1 भी उसी बैंक में है, तो बैंक तुरंत कार्रवाई कर सकता है, दूसरे बैंक का मामला होने पर आपका बैंक उस संबंधित बैंक से संपर्क कर फंड को होल्ड करने का जगहों पर क्यूआर कोड को स्कैन करते समय स्क्रीन पर आ रहे नाम

लालबागचा राजा के दर पर कोमल रानी संग दिखे गोविंदा, तो भड़की सुनीता आहूजा की बहू! बोलीं— ऐसे पुरुषों को...

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा बीते कई दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में गो. विंदा मुंबई में 'लालबागचा राजा' के दर्शन करते हुए देखे गए, जिसके बाद वे चर्चा में आ गए। उनके साथ कोमल रानी स्वर्णकार भी थीं, जो उनकी आने वाली फिल्म 'रूपा' में उनकी को-स्टार हैं। दोनों को बप्पा का आशीर्वाद लेते हुए देखा गया। कोमल का नाम गोविंदा के साथ डेब्यू की अफवाहों में भी जोड़ा जाता रहा है। अब, उनके साथ में दिखने के एक दिन बाद, कश्मीरा शाह ने इंस्टाग्राम पर 'घर तोड़ने वालों' का एक क्रिटिक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे पुरुषों को आदर्श मानना घबड़ा करे जो 'कम उम्र की लड़कियों' के लिए अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं।

बुधवार, 23 सितंबर को कश्मीरा शाह ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की तस्वीर में वह बाल, कनी खड़े चायवॉफी का आनंद लेती हुई दिख रही हैं। एक्ट्रेस ने इस तस्वीर को एक क्रिटिक नोट के साथ तोड़ा है, जिसे लोग गोविंदा और कोमल रानी से जोड़कर देख रहे हैं। नोट में लिखा, "मुझे यकीन नहीं होता कि लोग एक मिस्ट्री महिला को इतना ग्लैमरस दिखा रहे हैं और उसके बारे में पोस्ट कर रहे हैं। घर तोड़ने वालों को बढ़ावा देना बंद करें और उन पुरुषों को आदर्श मानना घबड़ा दें जो अपनी समर्पित पत्नियों को



छोड़कर कम उम्र की लड़कियों के साथ चले जाते हैं। यह धिनीना है। हमें अपने लोगों से ज्यादा समझदारी और नैतिकता की उम्मीद है। प्लीज इस पागलपन को रोकें। हालांकि कश्मीरा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी ये बातें गो. विंदा की पर्सनल लाइफ पर फिर से ध्यान खींचे जाने के बीच आई हैं। कश्मीरा के पति और गोविंदा के भतीजे, कृष्णा अभिषेक ने भी इस पोस्ट को 'लाइक' किया है।

इस बीच, कोमल रानी के साथ गो. विंदा के दिखने के एक दिन बाद उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। पैराजॉर्जी से बातपीत के दौरान उन्होंने इसानों के मुकाबले पालतू जानवरों के ज्यादा

वफादार होने के बारे में एक रहस्यमयी बात कही। उनकी यह बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। उन्होंने कहा, "जानवरों से प्यार करो, इसानों से नहीं। इसान धोखेबाज होते हैं। गोविंदा और सुनीता आहूजा ने 1987 में शादी की थी। इस कपल की शादी को 39 साल हो चुके हैं और उनके दो बच्चे हैं — टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा। खबरों के मुताबिक, गोविंदा और सुनीता ने इस साल की शुरुआत में तलाक के लिए अर्जी दी थी। हालांकि, सुनीता ने हाल ही में यह केंस वापस ले लिया, जब उन्हें पता चला कि गोविंदा एक्ट्रेस कोमल रानी से शादी करने की योजना बना रहे थे। लेकिन गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इस दावे को

द पैराडाइज रिव्यू: टिकट खरीदने से पहले जानें कैसी है नेचुरल स्टार नानी की फिल्म, पढ़ें क्या बोले दर्शक

द पैराडाइज रिव्यू: टिकट खरीदने से पहले जानें कैसी है नेचुरल स्टार नानी की फिल्म, पढ़ें क्या बोले दर्शक नानी स्टार फिल्म 'द पैराडाइज' सिनेमाघरों में भारी चर्चा और प्रशंसकों के उत्साह के बीच आज रिलीज हुई, लेकिन नकारात्मक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आने के साथ ही फिल्म को लेकर चर्चा का रुख तेजी से बदल गया। इस फिल्म ने नानी के करियर की सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग में से एक दर्ज की थी और नियमित शो से पहले ही दुनिया भर में 40 करोड़ रुपये से अधिक की प्री-सेल्स की रिलीज के रिव्यू आने के बाद दर्शकों का मन बदलता दिख रहा है।

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्म को निराशाजनक बताया और हाल ही में रिलीज हुई यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से इसकी तुलना करते हुए इसे कमतर बताया। कुछ ने नानी से बेहतर स्क्रिप्ट चुनने को कहा, वहीं कुछ ने फिल्म में राघव जुयाल की अभिनय पर सबाल उठाए। वहीं, कम से कम एक फैन ने आलोचना का खंडन करते हुए सबाल उठाया कि क्या फिल्म को 'पैसे देकर फैलाई गई नकारात्मकता' का सामना करना पड़ रहा है। एक यूजर ने लिखा, 'शुरु से अंत तक एक घटिया फिल्म, इस शुरुआत थोड़ी अच्छी है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा वाले भड़काऊ सीन लिखना भावनाओं को जगाने का तरीका नहीं है। कुछ मजेदार पलों के साथ, ये फिल्म बनावटी किरदारों से



भरी हैं। सरासर घटिया एक अन्य यूजर ने लिखा, 'फिल्म बेहद निराशाजनक है / छंउमपेछंदप कृपया जर्सी जैसी अच्छी स्क्रिप्ट चुनें। आप अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर रहे हैं।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'शुरुआती 16 मिनट को छोड़कर, पूरा आधा हिस्सा बिल्कुल बेकार था। फिर दूसरा आधा हिस्सा आया और हमें लगा कि लाइनर किटनी अच्छी फिल्म थी। रुनानी, आप बड़ी फिल्मों के लिए नहीं बने हैं। आप हाय नन्ना जैसी हल्की-फुल्की, भावनात्मक फिल्मों के लिए ही बने हैं।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'राघव जुयाल को द पैराडाइज में उनके अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए। माई को अभिनय का मतलब ही नहीं पता। कोई उन्हें इतनी बड़ी फिल्म में कैसे कास्ट कर सकता है? कितना घटिया अभिनय है।' एक अन्य टिप्पणी में कहा गया, 'रूजिमेंटकॉम के प्रीमियर के

बाद रुज्जुपव को सकारात्मक समीक्षाएं मिल रही हैं। एक अन्य पोस्ट में लिखा था, नानी के करियर की सबसे खराब फिल्म, आपदा एक फैन ने किया नानी को सपोर्ट आलोचनाओं के बीच एक फैन ने अभिनेता का बचाव करते हुए लिखा, 'यह अविश्वसनीय है कि नानी की फिल्म पैराडाइज को नकारात्मक समीक्षाएं मिल रही हैं। किसी ने तो यह भी कहा कि पैराडाइज 'टॉक्सिक' से भी बदतर है। वहीं किसी ने कहा कि पहला भाग अच्छा है लेकिन दूसरा भाग असहनीय है। क्या यह वाकई एक खराब फिल्म है या नानी की फिल्म के खिलाफ पैसे देकर फैलाई गई नकारात्मकता है? मुझे नानी और अनिरुद्ध के संगीत पर पूरा भरोसा है। 'आया शेर' मेरा इस समय का पसंदीदा गाना है। फिल्म के बारे में रिलीज से पहले ही, 'द पैराडाइज' ने एडवांस टिकट विक्री के जरिए नानी

'महाकाव्य श्री रामायण कथा' ट्रेलर: सीता की प्रतीक्षा बनी रावण का अंत, नए युग के आरंभ के लिए प्रभु राम ने लंकापति के खिलाफ छेड़ी जंग

हैदराबाद: 'कवा' बादाम वायरल गर्ल अंजली अरोड़ा इन दिनों सुर्खियों में हैं। वह पौराणिक फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' में माता सीता का किरदार निभा रही हैं। मेकर्स ने आज, 17 सितंबर को फिल्म का ट्रेलर जारी किया है। यह फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का ट्रेलर अपलोड किया और कैप्शन में लिखा, 'अधरम के आगू, धरम के नांव कृ श्री राम, महाकाव्य श्री रामायण कथा का ट्रेलर आउट।' इस फिल्म में देव शर्मा भगवान राम के रूप में, अंजलि अरोड़ा माता सीता के रूप में और रजनीश बुगल रावण के रूप में नजर आएंगे। साथ ही, शील वर्मा लक्ष्मण और निर्भय वाधवा हनुमान की भूमिका निभाएंगे। यह फिल्म भगवान राम की यात्रा को बड़े पर्दे पर पेश करती है, जिसके केंद्र में प्रेम, भक्ति, मर्यादा और धर्म जैसे भावुक पहलू हैं। ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर की शुरुआत सीता के अपहरण से होता है। इसके बाद अशोक नाटिका को सीता आता है, जहां रावण सीता का कहता है कि उनका बनवासी राम उन्हें बचाने नहीं आएगा, जिस पर सीता दुब्रता से कहती है कि प्रभु राम अवश्य आएंगे और उस दिन तुम्हारा



और तुम्हारे इस सोने की लंका का विनाश होगा, जिस पर रावण क्रोध में कहता है, असंभव है रावण का विनाश। इसके बाद राम और हनुमान के मिलन, हनुमान का लंका पहुंचना और माता सीता से मिलना, राम सेतु निर्माण, राम का अपनी सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान, रण भूमि समेत कई सीन दिखाए जाते हैं। ट्रेलर के आखिरी में राम और सीता के मिलन की झलक दिखाई जाती है। 'महाकाव्य

श्री रामायण कथा' का निर्देशन अभिषेक सिंह ने किया है, इसे प्रकाश महोदय और संजय बुंदेला ने प्रोड्यूस किया है, हनी कुलदीप अग्रवाल और मोनिका सेन इसके को-प्रोड्यूसर हैं। इसे एजे फिल्म एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के अजय कर्नोजिया ने पेश किया है। यह फिल्म 25 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

'नकजं जमत' ज्तंपसमत: पाकिस्तानी जासूस बना हिंदुस्तानी देशभक्त, हंस-हंसकर लोटपोट कर देगी आयुष्मान खुराना-सारा की फिल्म का ट्रेलर

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की आगामी स्पाई कॉमेडी फिल्म 'उड़ता तीर' दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तैयार है। बुधवार, 23 सितंबर को फिल्म का मजेदार ट्रेलर जारी किया गया है। यह फिल्म कॉमेडी, एक्शन और जासूसी का एक मजेदार मिश्रण होने का वादा करती है। जिसमें आयुष्मान का किरदार एक मिशन में फंस जाता है। धर्मा प्रोडक्शन ने 23 सितंबर को उड़ता तीर का ट्रेलर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड किया और कैप्शन में लिखा, 'पेश है जबरदस्त कॉमेडी, ऐसी जो पहले कभी नहीं देखी। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह मिशन एक रोलरकोस्टर



राइड जैसा है।' 'उड़ता तीर' का ट्रेलर 'उड़ता तीर' के ट्रेलर की शुरुआत पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिस से होता है। वॉयज ओवर में यह कहते

हुए सुना जा सकता है कि हिंदुस्तानी एक के एक जासूस पाकिस्तान में भेज रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान, हिंदुस्तान में अपना जासूस भेजगा। 3 मिनट 18 सेकंड के इस ट्रेलर में आयुष्मान खुराना को बिलाल अहमद के तौर पर दिखाया गया है, जो एक पाकिस्तानी जासूस है और उसे एक मिशन पर भारत भेजा जाता है। लेकिन, एक धमाके में बिलाल की याददास्त चली जाती है और कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अपनी पहचान को लेकर उलझन में रहने के बाद, आखिरकार



गुजरात में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' आकर्षण का केंद्र बनने के लिए तैयार है, क्योंकि 22 सितंबर को केवडिया के एकता नगर में 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रतिष्ठित समारोह के लिए आयोजन स्थल को मजबूत रूप दिया गया है, जहां मेहमानों के लिए एक बड़ा पंडाल, एयर-कंडीशंड डोंग और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह में पुरस्कार प्रदान करेंगी, जो दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इस बहुप्रतीक्षित समारोह से पहले बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुजरात पहुंच चुके हैं। 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह के लिए पूरे भारत से फिल्म स्टार्स गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर (केवडिया) पहुंचने लगे हैं। केवडिया पहुंचने वालों में से कार्तिक आर्यन एक थे। सोशल मीडिया पर कार्तिक का कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का वीडियो सामने आया है। नेशनल लेवल के समारोह में शामिल होने वाले कार्तिक का होटल में पारंपरिक तरीके से रूईस फीवर फिल्मों, नॉन-फीवर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन में उत्कृष्टता को मान्यता देने हैं। ये अवॉर्ड्स भारत की भाषाओं, क्षेत्रों और सिनेमाई रूपों की फिल्मों और फिल्म निर्माण को शामिल करते हैं।

2024 फिल्म वर्ष के प्रमुख सम्मानों में, 'आर्टिकल 370' को बेस्ट फीवर फिल्म के रूप में चुना गया है, जबकि 'भंगार' ने बेस्ट नॉन-फीवर फिल्म का पुरस्कार जीता है और 'राम-नामी' को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का नाम दिया गया है। ममूदी और कार्तिक आर्यन क्रमशः 'ब्रह्मयुगम' और 'चंदू चौपियन' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड शेयर करेंगे। वहीं, यामी गौतम को 'आर्टिकल 370' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में चुना गया है। वागत किया गया। ढोल-नगाड़ा, माला, आरती और तिलक लगाकर एक्टर का स्वागत किया गया। एक वीडियो में एक्टर को लोगों के साथ फोटो क्लिक भी कराते हुए देखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को 2024 के लिए भारतीय सिनेमा में उपलब्धियों के लिए अवॉर्ड्स देंगी। दिग्गज कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और पांच दशकों से अधिक के करियर के लिए 2024 का दादा साहब फाल्के अवॉर्ड मिलेगा, सरकार ने इस महीने की शुरुआत में दादा साहब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की सिफारिश पर इस पुरस्कार की घोषणा की थी।

954 में शुरू किए गए नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स फीवर फिल्मों, नॉन-फीवर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन में उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं। ये अवॉर्ड्स भारत की भाषाओं, क्षेत्रों और सिनेमाई रूपों की फिल्मों और फिल्म निर्माण को शामिल करते हैं। 2024 फिल्म वर्ष के प्रमुख सम्मानों में, 'आर्टिकल 370' को बेस्ट फीवर फिल्म के रूप में चुना गया है, जबकि 'भंगार' ने बेस्ट नॉन-फीवर फिल्म का पुरस्कार जीता है और 'राम-नामी' को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का नाम दिया गया है। ममूदी और कार्तिक आर्यन क्रमशः 'ब्रह्मयुगम' और 'चंदू चौपियन' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड शेयर करेंगे। वहीं, यामी गौतम को 'आर्टिकल 370' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में चुना गया है। रणदीप हुड्डा को 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' के लिए डायरेक्टर की बेस्ट डेब्यू फिल्म का अवॉर्ड्स मिलेगा। ये अवॉर्ड्स कई व्यावसायिक रूप से सफल और समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्मों को भी मान्यता देंगे। कलिक 2888 'व' ने बेस्ट पॉपुलर फिल्म का खिताब हासिल किया है। जबकि 'अमरन' को निर्देशक राजकुमार परियारामी के लिए बेस्ट डायरेक्शन का अवॉर्ड मिला है।